



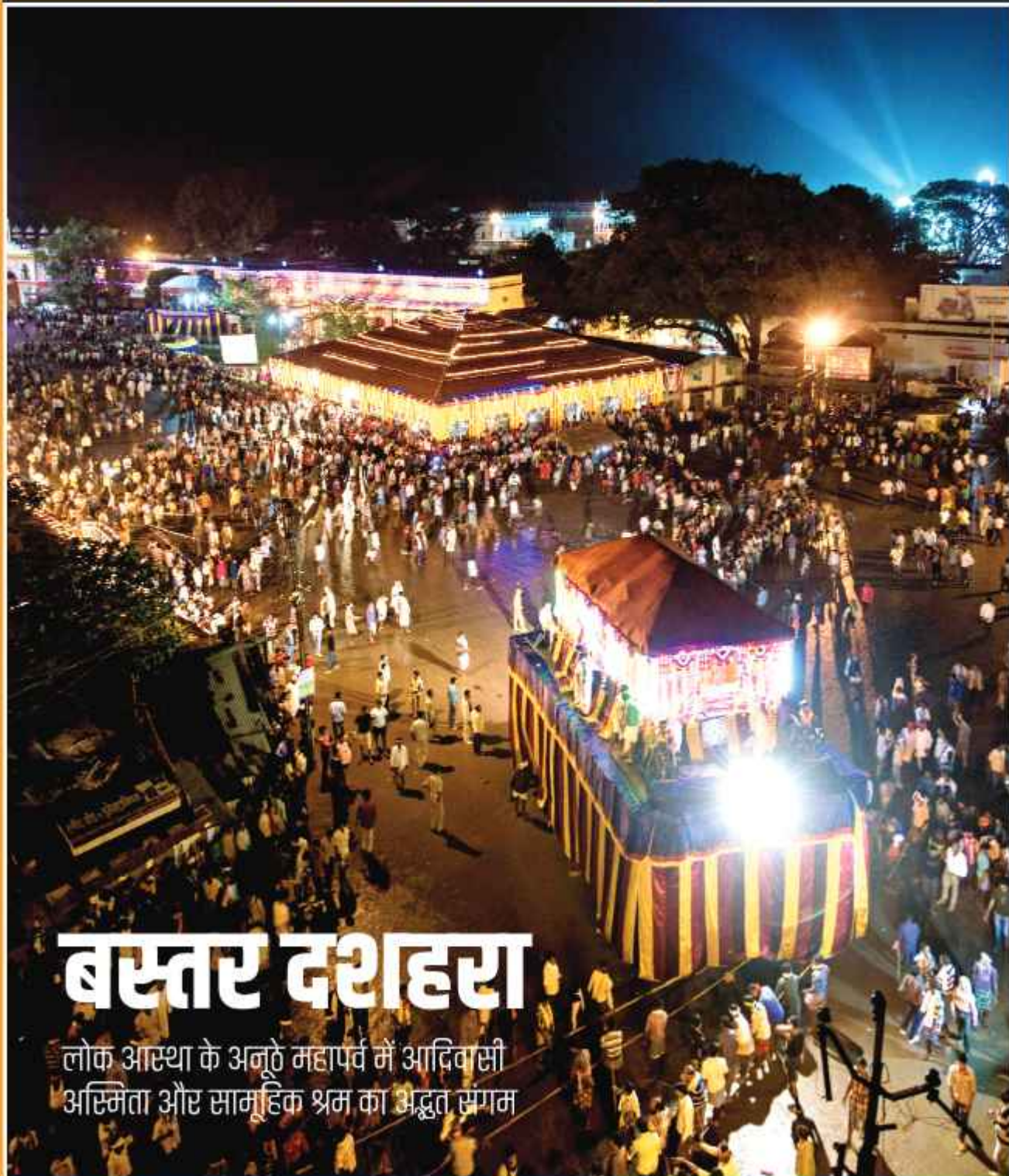
RNI : CTHIN/25/A3260

जनता के

गोठ

जहां खबर नहीं, असर होता है

• वर्ष : 02 • अंक : 1 • अक्टूबर 2026 • मूल्य : 25 रुपये



बस्तर दशहरा

लोक आस्था के अनूठे महापर्व में आदिवासी
अस्मिता और सामूहिक श्रम का अद्भुत संगम



जनता के गोठ

विजयादशमी
की हार्दिक
शुभकामनाएं



मासिक पत्रिका



IDEAL Marketing & Production
Government Documentary Film
Corporate Film
Presentation Film
Live Telecast Setup

www.jantakegoth.com

संपादक

शुभम वर्मा

सलाहकार संपादक

अनिल पुसदकर

ब्यूरो

अविनाश प्रसाद (बस्तर ब्यूरो) 97701 64499

भुजबल यथेल (बकावन, बस्तर) 62662 59437

ओमप्रकाश रजक (बकावेंद, बस्तर) 62615 58359

रोहित यादव (बलरामपुर) 79748 30818

चंद्रहास वैष्णव (जगदलपुर) 82238 99000

संजु जैन (वेमेतरा) 70008 85784

प्रेम दुर्गा (बीजापुर) 63032 84212

भूपेन्द्र सिंह राठौर (बिलासपुर) 75669 08440

जीतु साहू (धमतरी) 84352 38664

लोकेश्वर सिन्हा (गरियाबंद) 79748 44284

तनवीर आलम (गौरेला पेंडा मरवाही) 98930 22154

हेमंत पटेल (जांजगीर चांपा) 99265 12822

जितेंद्र सिंह (जशपुर) 94255 69910

उमेश कुमार यादव (कोरवा) 87706 46952

आकाश श्रीवास्तव (ब्यूरो, कोरवा जिला) 74706 89880

उग्रसेन पाल (मनेन्दगढ़ चिरमिरी भरतपुर) 96914 42556

त्रिलोक कोशले (मुंगेली) 83599 00249

जाह्नव अंसारी (सूरजपुर) 62685 23783

औचल कुमार वर्मा (उतई / पाटन) 78282 48170

संदीप मिश्रा (दुर्ग) 98934 50338

गोवर्धन लाल सिन्हा (राजनांदगाँव) 93037 88975

महयुव खान (कवधी) 81092 90209

ओमकार साहू (सिमगा, बलौदाबाजार) 93669 27970

मार्केटिंग एजीक्यूटिव

तरुण चंछोर 83498 38928

डिल्ली कुमार 96856 30335

LAYOUT **HITI**
Graphic 8827988255

कार्यालय

हाउस नंबर 411, देवनगरी, आदिवासी छात्रवास के सामने, शिवशंकर होटल के पीछे, महादेव पाट, रायपुर, रायपुर (छत्तीसगढ़)

प्रकाशक एवं संपादक : शुभम वर्मा हाउस नंबर 411, देवनगरी, आदिवासी छात्रवास के सामने, शिवशंकर होटल के पीछे, महादेव पाट, रायपुर, रायपुर (छत्तीसगढ़) से प्रकाशित एवं दैनिक भारत माल्य प्रेस, हाउस नंबर 855, पॉस्ट नंबर 09, अनांत विश्वरूपाय्य, रायपुर, रायपुर से मुद्रित।

संपर्क- शुभम वर्मा 8300870270, 9425520408, 977143 45242
RNI : CTHIN/25/A3260



06 सत्ता की अगली जंग की आहट



10 चार चुनावी राज्यों में कसौटी पर कांग्रेस



36 अभिनय नहीं, किरदार की आत्मा बन जाते...

12 सुशासन का सेतु बना मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का सेवा संकल्प

18 सेरिक टैंक का राज!

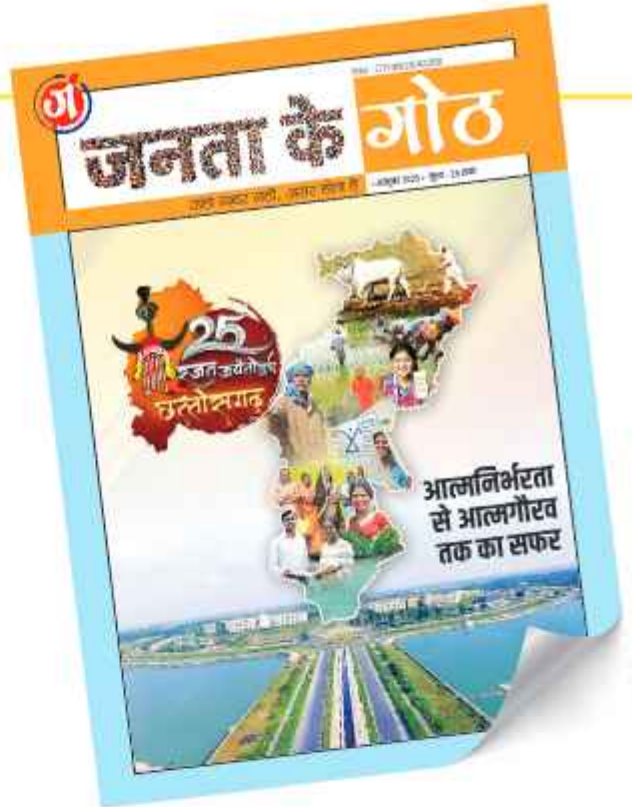
26 वोटर लिस्ट पर राजनीति

28 85 पदकों की चमक लेकिन सवाल भी बाकी

'जनता के गोठ' का पहला पड़ाव

कि

सी पत्रिका का जन्म लेना महज कुछ पन्नों को स्टाही से भर देना नहीं होता। यह विचारों को आकार देने, समाज के सवाल को स्वर देने और समय की उड़कनों को शब्दों में दर्ज करने का संकल्प होता है। 'जनता के गोठ' ने अपनी स्थापना के एक वर्ष पूरे करते हुए इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की है। यह पहला साल केवल समय की गणना नहीं, बल्कि विचार, विश्वास, मेहनत और जनसरोकारों के प्रति प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। आज जब सूचना के असीमित प्रवाह में खबरों की गति तो बढ़ी है, लेकिन कई बार उनकी गहराई पीछे छूट जाती है, तब एक ऐसी पत्रिका की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है, जो घटनाओं के शोर से आगे बढ़कर उनके अर्थ को समझने का प्रयास करे। पत्रकारिता का काम केवल यह बताना नहीं कि क्या हुआ, बल्कि यह भी सामने लाना है कि क्यों हुआ, उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा और उससे आम आदमी का जीवन किस तरह प्रभावित होता है। 'जनता के गोठ' की यात्रा का मूल भाव भी इसी जनपक्षधर पत्रकारिता की दिशा में आगे बढ़ना है। छत्तीसगढ़ की माटी में लोकजीवन की अपनी विशिष्ट पहचान है। वहाँ की संस्कृति, परंपराएं, संघर्ष, आकांक्षाएं और बदलाव की कहानियाँ समाज की वास्तविक पूंजी हैं। गांवों की चौपाल से लेकर शहरों की भागदौड़ तक, खेतों में पसीना बहाते किसानों से लेकर भविष्य के सपने संजोते युवाओं तक, महिलाओं के संघर्ष से लेकर वंचित तबकों की उम्मीदों तक, समाज का हर हिस्सा अपनी बात कहने का हकदार है। पत्रकारिता तभी सार्थक होती है, जब इन आवाजों को उचित स्थान मिले और उन सवालों को भी महत्व दिया जाए, जो अक्सर सुर्खियों की दौड़ में पीछे छूट जाते हैं। 'जनता के गोठ' के लिए पहला वर्ष अपनी पहचान गढ़ने, पाठकों से संवाद स्थापित करने और अपनी संपादकीय दिशा को मजबूत करने का अवसर रहा है।



यह शुरुआत जितनी उत्साहजनक है, उतनी ही जिम्मेदारियों का एहसास कराने वाली भी है। किसी प्रकाशन की असली उपलब्धि उसके प्रकाशित अंकों की संख्या से नहीं, बल्कि पाठकों के बीच अर्जित विश्वास, उसकी सामग्री की विश्वसनीयता और समाज के प्रति उसकी उपयोगिता से तय होती है। इसलिए वह अवसर आत्मप्रशंसा से अधिक आत्ममंथन का है। हम मानते हैं कि पत्रकारिता में निष्पक्षता का अर्थ सवालों से दूरी बनाना नहीं, बल्कि तथ्यों के आधार पर सवाल पूछने का साहस रखना है। सत्ता हो या व्यवस्था, नीति हो या उसका किर्यान्वयन, हर विषय को विवेक, प्रमाण और जनहित की कसौटी पर परखना पत्रकारिता का दायित्व है। इसी तरह, किसी विषय के सभी महत्वपूर्ण पक्षों को समझना, प्रभावित लोगों की बात सुनना और बिना पर्याप्त तथ्यों के निष्कर्ष पर पहुँचने से बचना भी उतना ही आवश्यक है। आलोचना का उद्देश्य केवल विरोध नहीं, बल्कि कमियों की पहचान कर सुधार की संभावनाओं को सामने लाना होना चाहिए। हमारे लिए पाठक केवल पत्रिका के ग्राहक नहीं, बल्कि इस वैचारिक यात्रा के सहभागी हैं। उनकी अपेक्षाएं हमें बेहतर सामग्री तैयार करने, नए विषयों को तलाशने और अपनी कमियों को सुधारने की प्रेरणा देती हैं। पत्रकारिता का यह रिश्ता तभी मजबूत होगा, जब संवाद एकतरफा न होकर परस्पर विश्वास पर आधारित



हो। इसी विश्वास को बनाए रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। पहले वर्ष की उपलब्धियों के साथ आगे की चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं। बदलते मीडिया परिवेश में तथ्यपरकता, भाषा की गरिमा, विषयों की विविधता और संपादकीय स्वतंत्रता को कायम रखना निरंतर साधना की मांग करता है। हमारा प्रयास रहेगा कि 'जनता के गोठ' जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता दे, स्थानीय समस्याओं और संभावनाओं को प्रमुखता से सामने लाए तथा सकारात्मक बदलाव की कहानियों को भी उतना ही स्थान दे, जितना जरूरी सवालों को। एक वर्ष पूरा होना मंजिल पर पहुंचना नहीं, बल्कि आगे की यात्रा के लिए नए संकल्प लेने का अवसर है। हम अपने पाठकों, सहयोगियों, शुभचिंतकों और उन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इस प्रयास को अपना स्नेह और विश्वास दिया। हमारा संकल्प स्पष्ट है। 'जनता के गोठ' को ऐसी पत्रकारिता का मंच बनाना, जहाँ जनता के सवालों को जगह मिले, तथ्यों की प्रतिष्ठा बनी रहे और समाज के हित सर्वोपरि हों। पहला वर्ष हमारी शुरुआत है; आने वाले वर्ष हमारी प्रतिबद्धता की असली परीक्षा होंगे। विश्वास की इस पूंजी को संजोते हुए हम एक ऐसी पत्रकारिता की ओर बढ़ना चाहते हैं, जो केवल समय का लेखा-जोखा न रखे, बल्कि अपने समय के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाए।

- शुभम वर्मा
संपादक

शुभम वर्मा: कैमरे के पीछे से संपादकीय नेतृत्व तक

राजपुर के पत्रकार शुभम वर्मा की पत्रकारिता यात्रा वर्ष 1998 में टेलीविजन न्यूज प्रोडक्शन, कैमरापर्सन और रिपोर्टिंग से शुरू हुई। पत्रकारिता की शुरुवात खबरों को समझ, तकनीकी दक्षता और प्रसारण की बारीकियों में रूचि ने उन्हें शुरुआती दौर में ही समाचार निर्माण के विभिन्न पहलुओं से जोड़ दिया। साल 1998 में अभी तक, फिर 1999 से 2001 तक अब तक टीवी न्यूज में काम करने के बाद उन्होंने आकाश चैनल में वर्ष 2001 से 2005 तक अपनी सेवाएं दीं। इसके बाद दिल्ली में उन्होंने दो साल तक नेशनल न्यूज चैनल में काम भी किया। साथ ही विभिन्न समाचार चैनलों में न्यूज पैकेज निर्माण और प्रोडक्शन से जुड़े दायित्व निभाते हुए उन्होंने अपने अनुभव को विस्तार दिया। साल 2005 से 2009 तक ग्रीड न्यूज में असिस्टेंट टीवी न्यूज प्रोड्यूसर और रिपोर्टर के रूप में काम करते हुए उन्होंने खबरों के संकलन, साक्षात्कार, रिपोर्टिंग और वीडियो संपादन में दक्षता हासिल की। वर्ष 2009 से 2013 तक बीटीवी में टीवी न्यूज प्रोड्यूसर और रिपोर्टर के रूप में उन्होंने समाचारों के निर्माण और प्रसारण की जिम्मेदारियाँ संभालीं। इसके बाद वर्ष 2013-14 में उत्तीसगढ़ के पहले सेटेलाइट चैनल जी24 एंटे उत्तीसगढ़ में वीडियो एडिटर के रूप में ज्वाइन किया। इसके बाद आईबीसी 24 उत्तीसगढ़-मध्य प्रदेश से जुड़े रहे। इसके बाद नेशनल न्यूज चैनल एचएनएन न्यूज के स्टेट हेड की जिम्मेदारी भी निभाई। सभी अनुभवों के बाद शुभम वर्मा ने अपनी खुद की मीडिया संस्थान की नींव रखी। उन्होंने डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की ओर धीरे-धीरे अपने कदम बढ़ाए। वर्तमान में वे आईएमपी 24 न्यूज वेबपोर्टल, दैनिक अखबार 'जनता के गोठ' और मासिक पत्रिका 'जनता के गोठ' के संपादक हैं। इस तरह, दो दशक से ज्यादा के अनुभव के साथ उनकी यात्रा समाचार निर्माण से संपादन और मीडिया संस्थानों के नेतृत्व तक पहुंची है।



सत्ता की अगली जंग की आहट

भाजपा और कांग्रेस के नए प्रभारियों के सामने संगठन को धार देने से लेकर जनता का भरोसा जीतने तक की चुनौती



छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 'भले ही अभी करीब दो साल दूर हो लेकिन प्रदेश की सियासत में चुनावी सरगर्मी अभी से तेज होने लगी है। 'भाजपा ने स्मृति ईरानी को प्रदेश संगठन का नया प्रभारी बनाकर अपनी चुनावी रणनीति को धार देने का संकेत दिया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने सुखदेव भगत को प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपकर संगठन को नए सिरे से सक्रिय करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। दोनों दलों के सामने चुनौती केवल चुनाव जीतने की नहीं है बल्कि ऐसी राजनीतिक जमीन तैयार करने की है जिस पर चुनाव के समय मजबूत जनसमर्थन की इमारत खड़ी की जा सके। राजनीति में दो साल का समय कम नहीं होता। इस दौरान सरकार के कामकाज का आकलन होता है। विपक्ष अपनी भूमिका तलाशता है। जनता की अपेक्षाएं बदलती हैं और संगठन की मजबूती या कमजोरी चुनावी नतीजों को प्रभावित करने लगती है। यही वजह है कि 'भाजपा और कांग्रेस दोनों ने समय रहते संगठनात्मक तैयारियों पर जोर देना शुरू कर दिया है। अब सवाल यह है कि नए प्रभारी अपने दलों को कितनी प्रभावी दिशा दे पाते हैं और उनकी रणनीति जमीनी राजनीति में कितना बदलाव ला पाती है।

भाजपा के सामने सत्ता के साथ संगठन को मजबूत रखने की चुनौती

'भाजपा के लिए छत्तीसगढ़ में स्थिति कांग्रेस से अलग है। पार्टी राज्य की सत्ता में है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार चला रही है। ऐसे में उसके सामने सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के साथ संगठन को लगातार सक्रिय बनाए रखने की दोहरी जिम्मेदारी है। सत्ता में रहने के दौरान संगठन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि सरकारी उपलब्धियों का संदेश केवल प्रचार तक सीमित न रहे बल्कि आम नागरिक के अनुभव में भी दिखे। स्मृति ईरानी को प्रदेश प्रभारी बनाए जाने को इसी व्यापक संगठनात्मक ज़रूरत के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। राष्ट्रीय राजनीति में उनकी पहचान और संगठनात्मक अनुभव 'भाजपा के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। लेकिन किसी प्रदेश का चुनावी समीकरण केवल राष्ट्रीय स्तर की लोकप्रियता से तय नहीं होता। इसके लिए स्थानीय मुद्दों की समझ, क्षेत्रीय नेतृत्व के साथ

समन्वय। कार्यकर्ताओं की सक्रियता और जनता की नब्ब पहचानने की क्षमता भी उतनी ही ज़रूरी होती है।

'भाजपा के सामने यह सुनिश्चित करने की चुनौती होगी कि सरकार और संगठन के बीच तालमेल बना रहे। बूथ स्तर तक कार्यकर्ता सक्रिय रहें। स्थानीय समस्याओं पर समय रहते ध्यान दिया जाए और सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तव में पाल लोगों तक पहुंचे। संगठन की ताकत तभी सार्थक होती है जब वह जनता की समस्याओं और सरकार की नीतियों के बीच प्रभावी संवाद का माध्यम बने। पार्टी को यह भी ध्यान रखना होगा कि सत्ता में होने से अपेक्षाएं बढ़ती हैं। जनता केवल घोषणाओं पर नहीं बल्कि उनके परिणामों पर भी नज़र रखती है। इसलिए आगामी चुनाव की तैयारी में 'भाजपा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कसौटी सरकार के कामकाज और संगठन की विश्वसनीयता के बीच संतुलन कायम करना होगा।

कांग्रेस के लिए नई कमान से आगे बढ़कर नई कार्यसंस्कृति ज़रूरी

कांग्रेस के सामने चुनौती अधिक जटिल है। प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभाते हुए पार्टी को न केवल सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने हैं बल्कि जनता के सामने एक विश्वसनीय विकल्प भी प्रस्तुत करना है। सुखदेव भगत को प्रदेश प्रभारी बनाए जाने से कांग्रेस के संगठनात्मक पुनर्गठन की उम्मीदें बढ़ी हैं। झारखंड की राजनीति में सक्रिय रहे भगत के सामने अब छत्तीसगढ़ की राजनीतिक परिस्थितियों को समझने और प्रदेश संगठन को एक साझा दिशा देने की जिम्मेदारी है।

किसी भी विपक्षी दल के लिए सबसे बड़ी चुनौती मुद्दों की कमी नहीं बल्कि मुद्दों को जनआंदोलन में बदलने की क्षमता होती है। बेरोजगारी। किसानों की समस्याएं। आदिवासी क्षेत्रों की ज़रूरतें। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं। स्थानीय विकास तथा सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे सवाल जनता के जीवन से जुड़े हैं। कांग्रेस को इन मुद्दों पर केवल बयान जारी करने के बजाय निरंतर संवाद और ठोस राजनीतिक कार्यक्रमों के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। सुखदेव भगत के सामने संगठन के अलग-अलग स्तरों के बीच समन्वय स्थापित करना भी महत्वपूर्ण होगा। प्रदेश नेतृत्व। विधायक। जिला इकाइयां और

बूथ स्तर के कार्यकर्ता यदि अलग-अलग दिशाओं में काम करेंगे तो किसी भी रणनीति का प्रभाव सीमित रह जाएगा। कांग्रेस को ऐसी कार्यसंस्कृति विकसित करनी होगी जिसमें स्थानीय कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाए। जिम्मेदारियां स्पष्ट हों और संगठन की गतिविधियों का नियमित आकलन किया जाए।

प्रभारी बदलने से संगठन की दिशा बदलने का अवसर जरूर मिलता है लेकिन स्थायी बदलाव के लिए नेतृत्व को विश्वास पैदा करना पड़ता है। कांग्रेस के लिए यही असली परीक्षा होगी। उसे यह साबित करना होगा कि नया नेतृत्व केवल बैठकों और दौरों तक सीमित नहीं है बल्कि पार्टी की जमीनी ताकत बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

बस्तर बनेगा सियासी परीक्षा की अहम जमीन

छत्तीसगढ़ की राजनीति में बस्तर का महत्व केवल भौगोलिक विस्तार तक सीमित नहीं है। यह आदिवासी समाज की आकांक्षाओं, प्राकृतिक संसाधनों, विकास की प्राथमिकताओं और सुरक्षा से जुड़े सवालों का महत्वपूर्ण केंद्र है। इसलिए भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए बस्तर में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करना रणनीतिक रूप से अहम है।

सुखदेव भगत का प्रदेश प्रभारी बनने के बाद बस्तर का तीन दिवसीय दौरा इस खेल को कांग्रेस की प्राथमिकताओं में रखने का संकेत देता है। राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियां भी पार्टी के लिए राजनीतिक अवसर पैदा कर सकती हैं। लेकिन किसी बड़े नेता का दौरा अपने आप में संगठन की मजबूती का प्रमाण नहीं होता। दौरे से पहले जनता के वास्तविक सवालों को समझना और उसके बाद उन सवालों पर लगातार काम करना अधिक महत्वपूर्ण है।

बस्तर में विकास की बहस को सड़क, बिजली, पानी और संचार सुविधाओं तक सीमित नहीं रखा जा सकता। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, वनाधिकार, स्थानीय संस्कृति और आदिवासी समुदायों की भागीदारी भी उतने ही जरूरी विषय हैं। यदि कांग्रेस इन सवालों पर स्पष्ट दृष्टिकोण और निरंतर जनसंपर्क विकसित करती है तो उसका राजनीतिक संदेश अधिक प्रभावी हो

सकता है।

भाजपा के लिए भी बस्तर कम महत्वपूर्ण नहीं है। उसे सरकार की योजनाओं और विकास संवेधों पहलों का लाभ लोगों तक पहुंचाने के साथ यह सुनिश्चित करना होगा कि स्थानीय समुदायों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से हो। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की रणनीति तभी सफल होगी जब कार्यकर्ता केवल चुनाव के समय नहीं बल्कि सामान्य दिनों में भी जनता के बीच उपलब्ध रहें।

बस्तर की राजनीति में किसी भी दल की सफलता का आकलन केवल रैलियों की भीड़ से नहीं बल्कि स्थानीय विश्वास और निरंतर जनसंपर्क से किया जाना चाहिए। यहां राजनीतिक दावों की असली परीक्षा जमीन पर होगी।

बूथ की मजबूती ही तय करेगी चुनावी बढ़त

चुनावी राजनीति में बड़े नेताओं की सभाएं और प्रदेश स्तर की रणनीतियां तभी परिणाम देती हैं जब उनका असर बूथ तक दिखाई दे। भाजपा की चुनावी कार्यशैली में बूथ प्रबंधन और कार्यकर्ता नेटवर्क महत्वपूर्ण रहे हैं। कांग्रेस के लिए भी बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना अनिवार्य है। केवल प्रदेश मुख्यालय में बैठकर बनाई गई रणनीति से चुनावी सफलता सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

भाजपा को अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता बनाए रखने के साथ स्थानीय स्तर पर उठने वाली नाराजगी को भी समझना होगा। कांग्रेस को अपने परंपरागत जनाधार को फिर से सक्रिय करने और नए मतदाताओं के बीच भरोसा कायम करने की जरूरत होगी। दोनों दलों को यह देखना होगा कि उनके स्थानीय नेता जनता के बीच कितने स्वीकार्य हैं और संगठन के भीतर संवाद कितना प्रभावी है।

यही वह मोर्चा है जहां नए प्रभारियों की वास्तविक क्षमता सामने आएगी। संगठनात्मक बैठकों की संख्या से अधिक महत्वपूर्ण यह होगा कि बैठकों के फैसलों पर कितना अमल हुआ। कितने कार्यकर्ता सक्रिय हुए। जनता की शिकायतों पर कितनी कार्रवाई हुई और पार्टी के संदेश को कितने प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाया गया।



असली मुकाबला जनता के भरोसे का

भाजपा और कांग्रेस की तैयारियों में अंतर साफ है। भाजपा को सता में रहते हुए अपने कामकाज का ठोस हिसाब जनता के सामने रखना होगा। कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका से आगे बढ़कर भरोसेमंद विकल्प के रूप में अपनी पहचान मजबूत करनी होगी। एक दल के पास सरकार चलाने का अनुभव और उपलब्धियों का दावा है तो दूसरे के पास सरकार को चुनौती देने और वैकल्पिक नीतियां प्रस्तुत करने का अवसर है। दोनों दलों के लिए सबसे बड़ी भूल यह होगी कि वे चुनाव को केवल जातीय समीकरणों, नेताओं की लोकप्रियता और राजनीतिक आरोपों तक सीमित कर दें। मतदाता के लिए महंगाई, रोजगार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय विकास जैसे सवाल प्रथम महत्व रखते हैं। इन मुद्दों पर स्पष्ट नीति और दिश्वसनीय किराब्यन ही राजनीतिक दावों को वास्तविक समर्थन में बदल सकते हैं। स्मृति ईरानी के सामने भाजपा के संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की चुनौती होगी।

बस्तर दशहरा

अनूठे महापर्व में आस्था, आदिवासी अस्मिता और सामूहिक श्रम का अद्भुत संगम

दे

ख के अधिकांश हिस्सों में दशहरा 'भगवान राम की रावण पर विजय के रूप में मनाया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बस्तर में इस पर्व की पहचान बिल्कुल अलग है। यहां न रावण का पुतला जलता है, न रामलीला के मंचन से उत्सव की पहचान बनती है। यहां दशहरा मां दंतेश्वरी की आराधना, सैकड़ों गांवों की सहभागिता और पीढ़ियों से चली आ रही आदिवासी परंपराओं का महापर्व है। लगभग 75 दिनों तक चलने वाला यह आयोजन केवल धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि बस्तर के सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक स्मृति और सामूहिक शक्ति का जीवंत दस्तावेज है। जगदलपुर में मनाए जाने वाले बस्तर दशहरा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें परंपरा के केंद्र में राजपरिवार से अधिक व्यापक लोकसमाज की भागीदारी दिखाई देती है। पर्व के अलग-अलग चरणों में ग्रामीण समुदाय, पारंपरिक पदाधिकारी, कारीगर, पुजारी और विभिन्न गांवों के प्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। यही सहभागिता इसे देश के दूसरे दशहरा आयोजनों से अलग पहचान देती है।

राम-रावण की कथा से अलग शक्ति उपासना का पर्व

बस्तर दशहरा का संबंध रामायण की विजयादशमी परंपरा से नहीं है। यह बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी और अंचल के दूसरे देवी-देवताओं के प्रति सामूहिक श्रद्धा की अभिव्यक्ति है। यहां की धार्मिक परंपरा में शक्ति उपासना का विशेष स्थान है। इसलिए पर्व का मूल भाव रावण का नहीं, बल्कि देवी की आराधना, लोककल्याण की कामना और समुदाय की एकजुटता है। आदिवासी जीवन में प्रकृति, कृषि, पशुधन और पारिवारिक सुख का गहरा संबंध धार्मिक विश्वासों से रहा है। इन्हीं विश्वासों से त्योहारों, मेलों, नृत्य और संगीत की परंपराएं विकसित हुईं। बस्तर दशहरा में आस्था के साथ उल्लास भी जुड़ा है और व्यक्तिगत विश्वास सामूहिक उत्सव का रूप ले लेता है। इस पर्व को केवल धार्मिक मान्यताओं के चरम से देखना भी इसकी व्यापकता को सीमित कर देगा। इसके भीतर समाज की संगठन क्षमता, पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक निरंतरता के अनेक सूत्र मौजूद हैं।



राजा पुरुषोत्तम देव से जुड़ी ऐतिहासिक परंपरा

बस्तर दशहरा की रथयात्रा की शुरुआत का संबंध चालुक्य वंश के राजा पुरुषोत्तम देव से जोड़ा जाता है। प्रचलित जनश्रुति के अनुसार, राजा अपनी प्रजा और सैन्यदल के साथ जगन्नाथपुरी की यात्रा पर गए थे। वहां जगन्नाथ स्वामी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के बाद उन्हें सोलह पहियों वाला रथ प्रदान किया गया और 'लहुरी रथपति' की उपाधि मिली। परंपरागत विवरणों के अनुसार, राजा ने रथ के चार पहिए भगवान जगन्नाथ को समर्पित किए और शेष बारह पहियों का रथ मां देवश्री की आराधना के लिए निर्धारित किया। समय के साथ रथ निर्माण और परिक्रमा की व्यवस्था में बदलाव हुए। बाद में चार पहियों वाले फूल रथ और आठ पहियों वाले विजय रथ की परंपरा विकसित हुई। इन विवरणों में इतिहास के साथ जनश्रुतियों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यही वजह है कि बस्तर दशहरा केवल राजवंश की स्मृति नहीं, बल्कि लोकविश्वास और ऐतिहासिक परंपरा के मेल से विकसित हुआ उत्सव है।

पाठ यात्रा से शुरू होती हैं तैयारियों की यात्रा

बस्तर दशहरा की तैयारियां हरियाली अमावस्या के आसपास होने वाली पाठ यात्रा से शुरू होती हैं। इस रस्म में रथ निर्माण के लिए लाई गई लकड़ी के विशेष कुंदे, जिसे स्थानीय परंपरा में 'दुरलु खोदला' कहा जाता है, की पूजा की जाती है। औजारों की आराधना के साथ पर्व के निर्विघ्न आयोजन की कामना की जाती है। इसके बाद डेरी गड़ाई की रस्म होती है। साल की लकड़ी से बने शाखायुक्त स्तंभ को पारंपरिक विधि से स्थापित किया जाता है। इस अनुष्ठान के साथ रथ निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है और निर्धारित गांवों के कारीगर तथा ग्रामीण अपनी जिम्मेदारियों में जुट जाते हैं। इन रस्मों का महत्व केवल धार्मिक नहीं है। इनके माध्यम से आयोजन की सामूहिक तैयारी शुरू होती है और अलग-अलग गांवों की भूमिका फिर से सक्रिय हो जाती है।

लोकविश्वास के विशिष्ट रूप काछिन गादी और जोगी बिठाई

बस्तर दशहरा की प्रमुख रस्मों में काछिन गादी का विशेष स्थान है। काछिन देवी की आराधना के दौरान कांठों से बने आसन पर देवी का प्रतीकात्मक विराजना पर्व की अनुमति और आशीर्वाद से जुड़ा माना जाता है। परंपरा के अनुसार, माहरा समुदाय की एक बालिका में देवी का प्रभाव माना जाता है और उसके माध्यम से आयोजन की स्वीकृति प्राप्त की जाती है। यह रस्म बस्तर की सामाजिक संरचना का एक महत्वपूर्ण पक्ष भी सामने लाती है। देवी की अनुमति के बिना पर्व शुरू न करने की मान्यता में उन समुदायों को भी केंद्रीय स्थान मिलता है, जिनकी भूमिका समाज की पारंपरिक व्यवस्था में विशिष्ट रही है। इसी तरह जोगी बिठाई में हल्वा समुदाय का एक व्यक्ति नौ दिनों तक साधना और उपवास करता है। यह अनुष्ठान पर्व के सफल समापन की कामना से जुड़ा है। नवमी पर जोगी उठाई के साथ उसकी साधना पूरी होती है। इन रस्मों में धर्म, अनुशासन और सामूहिक आस्था का मेल दिखाई देता है।

विशाल रथ, सैकड़ों हाथ और परंपरागत कौशल

बस्तर दशहरा का सबसे आकर्षक दृश्य विशाल काष्ठ रथों की परिक्रमा है। इन रथों का निर्माण आधुनिक मशीनों के बजाय पारंपरिक औजारों और पीढ़ियों से विकसित कारीगरी के सहारे किया जाता है। बसुला, कुल्हाड़ी और दूसरे परंपरागत औजारों से लकड़ी को आकार देने में बड़ी संख्या में ग्रामीण कारीगर जुटते हैं। रथ निर्माण में साल और तिनसा जैसी लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। अलग-अलग हिस्सों के लिए निर्धारित गांवों के लोग सामग्री जुटाने से लेकर निर्माण तक की जिम्मेदारी निभाते हैं। रथ को खींचने का काम भी परंपरागत रूप से अलग-अलग समुदायों और गांवों में बंटा हुआ है। यह व्यवस्था सामूहिक श्रम का असाधारण उदाहरण है। इतने विशाल रथ को सुरक्षित ढंग से आगे बढ़ाने के लिए तालमेल, अनुशासन और परस्पर विश्वास जरूरी है। यहां किसी एक व्यक्ति का कौशल पर्याप्त नहीं होता; पूरी व्यवस्था तभी सफल होती है, जब हर सहभागी अपनी भूमिका निभाए।



फूल रथ से भीतर रैनी और बाहर रैनी तक

फूल रथ की परिक्रमा के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण रस्मों के सहारे रथ खींचते हैं। इसके बाद विजयादशमी पर आठ पहियों वाले विशाल विजय रथ की परिक्रमा होती है, जिसे भीतर रैनी कहा जाता है। परंपरा के अनुसार, रथ को बाद में कुम्हड़ाकोट ले जाया जाता है, जहां विभिन्न क्षेत्रों से आए देवी-देवताओं के प्रतीकों का समग्र होना है। इसके अगले चरण को बाहर रैनी कहा जाता है। इन आयोजनों में पूजा, नए अन्न की परंपरा और लोकसमुदाय की भागीदारी विशेष महत्व रखती है। मावली परछाव में देववाड़ा से आने वाली मावली देवी को अगवानी की जाती है। वहीं निशा यात्रा, कुंवारी पूजा, कुटुम्ब यात्रा और देवी-देवताओं की विदाई पर्व के अलग-अलग चरणों को पूरा करते हैं। मुरिया दरबार भी इस आयोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी ऐतिहासिक परंपरा में ग्रामीण प्रतिनिधियों और शासन के बीच जनसमस्याओं पर चर्चा होती रही है। इस तरह दशहरा धार्मिक आयोजन के साथ सामाजिक संवाद का मंच भी बनता है।

परंपरा की असली शक्ति है लोकसमाज

बस्तर दशहरा की पहचान उसकी अवधि, विशाल रथों या विशिष्ट रस्मों तक सीमित नहीं है। इसकी असली ताकत उस लोकसमाज में है, जो पीढ़ियों से इस आयोजन को जीवित रखे हुए है। समय के साथ शासन व्यवस्था, सामाजिक परिस्थितियों और उत्सव के स्वरूप में बदलाव आए हैं, लेकिन ग्रामीणों की सहभागिता इसकी केंद्रीय विशेषता बनी हुई है। वह पर्व बताता है कि किसी संस्कृति की निरंतरता केवल उसके अनुष्ठानों से नहीं, बल्कि उन लोगों से बनती है जो उन्हें अर्थ देते हैं। बस्तर दशहरा में आदिवासी समाज दर्शक नहीं, आयोजन का सक्रिय निर्माता है। लकड़ी चुनने से लेकर रथ गढ़ने, उसे खींचने और देवी-देवताओं की अगवानी तक उसकी भूमिका निष्ठापूर्वक रहती है। इसीलिए बस्तर दशहरा को केवल आस्था का उत्सव कहना पर्याप्त नहीं। यह सामूहिक श्रम, सामाजिक साझेदारी और सांस्कृतिक पहचान का ऐसा उदाहरण है, जिसमें अतीत की परंपराएं वर्तमान के जीवन से जुड़ी रहती हैं। राखण के पुतले के बिना मनाया जाने वाला यह दशहरा अपनी विशिष्टता से यही संदेश देता है कि भारत की सांस्कृतिक विविधता को सबसे बड़ी ताकत उसकी स्थानीय परंपराओं और उन्हें जीवित रखने वाले समुदायों में निहित है।

चार चुनावी राज्यों में कसौटी पर कांग्रेस

चार राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले ही हाईकमान के सामने घर संभालने की चुनौती

2 027 का विधानसभा चुनाव अभी सामने नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लिए उसकी तैयारी का समय शुरू हो चुका है। जिन राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां पार्टी के सामने केवल सत्ताह्वे दल से मुकाबले की चुनौती नहीं है, बल्कि कई जगह संगठन के भीतर के मतभेद भी चुनावी तैयारी की गति को प्रभावित कर रहे हैं। पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और गुजरात में विवादों की प्रकृति अलग-अलग है, लेकिन एक समानता साफ दिखाने देती है: स्थानीय नेतृत्व, संगठन और चुनावी रणनीति को लेकर स्पष्टता की तलाश। कांग्रेस हाईकमान ने कई जगह अलग-अलग नेताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियां देकर संतुलन बनाने की कोशिश की है।

पंजाब में प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को बनाए रखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को चुनाव अभियान समिति की जिम्मेदारी दी गई। बाद में पंजाब के प्रभारी के रूप में सचिन पायलट ने बिना मुख्यमंत्री चेहरे के सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही। यह व्यवस्था तत्काल टकराव को सीमित करने का प्रयास जरूर है, लेकिन इससे मूल प्रश्न खत्म नहीं होता कि चुनावी अभियान का राजनीतिक चेहरा कौन होगा और अंतिम निर्णय लेने की स्पष्ट कमान किसके पास रहेगी। इन चार राज्यों की स्थितियां यह संकेत देती हैं कि कांग्रेस के सामने केवल चुनावी मुद्दे तय करने की चुनौती नहीं है। उससे पहले उसे यह तय करना होगा कि संगठन में निर्णय की प्रक्रिया कितनी स्पष्ट होगी, स्थानीय नेताओं को कितनी राजनीतिक जगह मिलेगी और अलग-अलग महत्वाकांक्षाओं को एक चुनावी रणनीति में कैसे बदला जाएगा। हाईकमान के लिए सबसे कठिन काम शायद यही है कि वह किसी एक धड़े को पूरी तरह आगे बढ़ाए बिना संतुलन बनाए रखे। लेकिन संतुलन और असमंजस के बीच अंतर बहुत महान होता है। पंजाब में मुख्यमंत्री चेहरे का विवाद, उत्तराखंड में सामूहिक नेतृत्व की कवायद, उत्तर प्रदेश में गठबंधन की जरूरत और गुजरात में संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर उठे सवाल कांग्रेस के सामने अलग-अलग रूप में वही चुनौती रखते हैं। 2027 के चुनाव में अभी समय है। इसलिए इन मतभेदों को अंतिम चुनावी तस्वीर मानना जल्दबाजी होगी। लेकिन यह भी उतना ही स्पष्ट है कि चुनावी राजनीति में संगठन को आखिरी समय में जोड़ा नहीं जा सकता। कांग्रेस के लिए अगले कुछ महीने इस लिहाज से महत्वपूर्ण होंगे कि वह इन विवादों को केवल प्रबंधित करती है या उन्हें संगठनात्मक स्पष्टता और साझा रणनीति में बदल पाती है। फिलहाल चार राज्यों की राजनीति एक ही सवाल पूछ रही है: क्या कांग्रेस चुनाव से पहले अपने भीतर की आवाजों को एक राजनीतिक स्वर में बदल पाएगी?



पंजाब में चेहरे की राजनीति



पंजाब कांग्रेस में सबसे ज्यादा चर्चा मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर हुई। चन्नी समर्थक उन्हें 2027 के लिए मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने की मांग करते रहे हैं। दूसरी ओर प्रदेश संगठन में राजा वड़िंग और विधायक दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा की अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। जुलाई में पार्टी ने वड़िंग को प्रदेश अंतरिम बनाए रखा, बाजवा को विधायक दल के नेता की जिम्मेदारी दी और चन्नी को चुनाव अभियान समिति का अंतरिम बनाया। इसके बाद भी चन्नी समर्थकों की ओर से मुख्यमंत्री चेहरे की मांग सार्वजनिक रूप से उठती रही। सितंबर में सचिन पायलट के नेतृत्व में पार्टी ने सामूहिक नेतृत्व और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री तय करने की नीति को आगे बढ़ाया।

उत्तराखंड में नेतृत्व की तलाश

उत्तराखंड की तस्वीर पंजाब के मुकाबले थोड़ी अलग है। यहां चुनौती किसी एक चेहरे को लेकर विवाद से ज्यादा कई वरिष्ठ नेताओं के बीच राजनीतिक संतुलन बनाने की है। कांग्रेस ने चुनावी तैयारियों के लिए 23 सदस्यीय राजनीतिक मामलों की समिति गठित की है, जिसमें प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष राधापाल आर्य समेत वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है। ऐसी समितियां सामूहिक निर्णय का रास्ता खोल सकती हैं, लेकिन चुनावी राजनीति में संगठनात्मक विस्तार के साथ एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश भी जरूरी होता है। यदि नेतृत्व का संदेश कार्यकर्ताओं और मतदाताओं तक एक स्वर में नहीं पहुंचता, तो संगठनात्मक गतिविधियां भी अपना पूरा असर नहीं दिखा पातीं।



यूपी में गठबंधन का सवाल

उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लिए चुनौती और जटिल है। यहां पार्टी को एक तरफ अपने संगठन को मजबूत करना है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के साथ संबंध और सीट बंटवारे की दिशा भी तय करनी है। कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने सम्मानजनक और बराबरी की सीट साझेदारी की बात कही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और राजेंद्र गौतम दोनों ने सार्वजनिक रूप से सपा के साथ गठबंधन को लेकर सकारात्मक रुख जताया है। लेकिन कांग्रेस के भीतर गठबंधन को लेकर बहस केवल सीटों तक सीमित नहीं है। असली सवाल यह है कि लंबे समय तक दूसरे दल के संगठन पर निर्भर रहने की स्थिति में कांग्रेस अपने स्वतंत्र जनाधार और संगठन को किस तरह मजबूत करेगी। 2027 के चुनाव में गठबंधन कितना व्यापक होगा और कांग्रेस को कितनी राजनीतिक जगह मिलेगी, यह आने वाले महीनों में महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा।

गुजरात में संगठनात्मक टकराव

गुजरात में संकट का दूसरा रूप सामने आया है। पाटण में अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस के दो विधायकों जिग्नेश मेवाणी और किरीट पटेल के बीच मतभेद सार्वजनिक हुए। विवाद के बाद स्थानीय कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए। किरीट पटेल ने भी कार्यकर्ताओं और निर्वाचित प्रतिनिधियों से परामर्श की जरूरत पर जोर दिया। बाद में मेवाणी और पटेल के बीच सार्वजनिक बयानबाजी ने इस विवाद को और चर्चा में ला दिया। पार्टी प्रदेश नेतृत्व ने इसे आंतरिक मामला बताते हुए संवाद के जरिए सुलझाने की बात कही।



रांजगाँव मेला-2026

दिनांक: 7-8 अक्टूबर 2026



सुशासन का सेतु बना मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का सेवा संकल्प

योजनाओं से जीवन तक : छत्तीसगढ़ में सेवा संकल्प अभियान और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता सुशासन

शा सकीय योजनाएं तब सार्थक होती हैं, जब वे फाड़लों और कार्यालयों से निकलकर आम आदमी के जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। किसी जरूरतमंद परिवार को पक्की छत मिलती है, किसी महिला के हाथ में अपनी जरूरतों के लिए आर्थिक संबल आता है, किसी किसान के खेत तक पानी पहुंचता है और किसी कुपोषित बच्चे की सेहत लौटती है। तब जनसेवा का असली अर्थ सामने आता है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में चल रहा 'सेवा संकल्प अभियान 2026' इसी सोच को जमीन पर उतार रहा है। इसमें सुरक्षित आवास, सुलभ सेवाएं, सशक्त महिलाएं, स्वस्थ बच्चे, समृद्ध किसान और आत्मनिर्भर पशुपालक सभी के लिए योजनाएं बनी हैं, और उनकी सफलता का पैमाना आंकड़े नहीं, नागरिक के जीवन में आया बदलाव है।

कच्ची दीवारों से पक्के सपनों तक

अपना पक्का घर केवल ईंट और सीमेंट नहीं होता। वह सुरक्षा, सम्मान और भविष्य के भरोसे का नाम है। सरगुजा के पहाड़ी कोरवा परिवारों तक पीएम जनमन के जरिए आवास पहुंचा है। मोहन राम जैसे परिवार बरसों तक बारिश में टपकती छत और बच्चों की सुरक्षा की चिंता में जीते रहे। अब उनके

जीवन में नया भरोसा जुड़ा है। मोटू राम को हर साल की लिपाई-पुताई और नरमत्त की परेशानी से मुक्ति मिली है। उदयपुर श्वेल के हुडकू राम, बिरसू, रतन साय और छन्दू के गृह प्रदेश की खुशी बताती है कि आवास योजना की उपलब्धि ईंट-गारे की गिनती भर नहीं है। पक्की छत बच्चों को पढ़ाई का बेहतर माहौल, महिलाओं को सुरक्षित स्थान और पूरे परिवार को नोसम की मार से बचाव देती है।

महतारी वंदन से मिला आर्थिक संबल

महिला सशक्तिकरण परिवार और समाज के विकास की बुनियाद है। महतारी वंदन योजना में पाठ महिलाओं को हर माह आर्थिक सहायता मिलती है। इसे कोई बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करती है, कोई पोषण पर, कोई घर की जरूरतों पर तो कोई छोटे रोजगार की सामग्री पर। सरगुजा की राखी इसका उदाहरण है। पति के निधन के बाद दो छोटे बच्चों की जिम्मेदारी उन पर है। वे खेती के साथ सिलाई करती हैं और योजना की राशि बच्चों के पोषण और सिलाई सामग्री पर लगाती हैं। इस सहायता का महत्व राशि से ज्यादा उस भरोसे में है जो महिला को अपने परिवार के लिए खुद निर्णय लेने का अवसर देता है। आर्थिक निर्णय की ऐसी छोटी स्वतंत्रताएं ही आत्मविश्वास को मजबूत करती हैं।

दफ्तर नहीं, नागरिक के करीब पहुंचता शासन

सुशासन का अर्थ है कि सेवा के लिए नागरिक को शासन तक नहीं दौड़ना पड़े, शासन खुद उस तक पहुंचे। 'सेवा सेतु' ने कई सरकारी सेवाओं को एक डिजिटल मंच पर ला दिया है। ऑनलाइन आवेदन, आवेदन की स्थिति की जानकारी, डिजिटल प्रमाण पत्र और वसूली आधारित सत्यापन से प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हुई है। ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में छोटी-छोटी जरूरतों के लिए बार-बार दफ्तर जाने की मजबूरी छूट रही है। अम्बिकापुर की डॉली गंध के आगर कांड में नाम की त्रुटि थी। इस कारण उनका बैंक खाता और छात्रवृत्ति की प्रक्रिया अटकती हुई थी। सेवा सेतु से त्रुटि सुधरी और आगे का रास्ता खुल गया। सरगुजा की छात्र आराधना सिंह की जन्मतिथि सुधार की समस्या सीएम हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से हल हुई और उनकी उच्च शिक्षा की प्रक्रिया आसान हुई। समस्या भले एक दस्तावेज की थी, पर उसके समाधान ने शिक्षा, बैंकिंग और अवसरों के दरवाजे खोल दिए। डिजिटल सुशासन की सार्थकता यही है।

बस्तर: बदलाव की नई इबारत

जो बस्तर कभी हिंसा और उमारों के लिए जाना जाता था, वहाँ अब बदलाव की कहानी लिखी जा रही है। उच्च शिक्षा के बजट में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। छु लो आसमान, 'डानमुड़ी' और 'रमर लहर' जैसी पहलों से ग्रामीण विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग और आर्थिक सहायता मिल रही है। जगदलपुर के शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय को PM-USHA की 'मेरू' योजना से 100 करोड़ रुपये का अनुदान मिला है। इससे शोध केंद्र, प्रयोगशालाएँ, डिजिटल लाइब्रेरी और कौशल विकास केंद्र बन रहे हैं। यहाँ 20 नए अख्यारण विभाग शुरू हुए हैं और फार्मसी, विधि तथा शारीरिक शिक्षा जैसे रोजगारपरक पाठ्यक्रमों के साथ 4-वर्षीय ITET की शुरुआत हो रही है। सेवा संकल्प केवल जगदलपुर तक सीमित नहीं है। अंचल के शासकीय महाविद्यालयों के लिए 66 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। काकतीय पीजी कॉलेज जगदलपुर और इंदरु कैपट कन्या महाविद्यालय कांकेर को 5-6 करोड़ रुपये मिले हैं। नगरनार और किलेपाल जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में नए महाविद्यालय खुले हैं, ताकि जनजातीय बच्चों को पढ़ाई के लिए दूर न जाना पड़े। जहाँ कभी बंदूक की गूँज थी, वहाँ अब किताबों के पन्ने पलटने की आवाज सुनाई देती है।

कुपोषण से सुपोषण तक

जनकल्याण का सबसे संवेदनशील चेहरा बच्चों की सेहत में दिखता है। अम्बिकापुर के राधुनाथ जिला चिकित्सालय का पोषण पुनर्वास केंद्र गंभीर कुपोषित बच्चों के उपचार में लगा है। शिवाशी, रश्मि, प्रतीक और युवराज जैसे बच्चों के वजन में दृढ़ बढ़ोतरी बेहतर पोषण और उपचार का संकेत है। लड़ाई अस्पताल के बिस्तर पर खत्म नहीं होती। माता-पिता को पोषण, स्वच्छता, स्तनपान, पूरक आहार और निरमित निगरानी की जानकारी देना भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और परिवार का तालमेल इस व्यवस्था को मजबूत करता है। एक बच्चे को कुपोषण से बाहर निकालना आने वाली पीढ़ी में निवेश है।

बिहान से आत्मनिर्भरता, लखपति दीदी की पहचान

सहायता से आगे बढ़कर स्थायी आजीविका देने में स्व-सहायता समूह अहम भूमिका निभा रहे हैं। 'बिहान' के जरिए महिलाएं बचत, ऋण, प्रशिक्षण और आय बढ़ाने वाली गतिविधियों से जुड़ रही हैं। अम्बिकापुर की कल्पना सिंह ने समूह से ऋण लेकर खीर की खेती शुरू की और फिर बैंगन, टमाटर और तरबूज तक उत्पादन बढ़ाया। उन्हें बैंक, बाजार और खेती के काम खुद संभालने का आत्मविश्वास भी मिला। उदरपुर की मति बाई ने समूह से जुड़कर मुर्गी पालन को व्यवसाय बनाया। कभी मजदूरी पर निर्भर उनका परिवार आज इसी से आय अर्जित कर रहा है। सरगुजा का 'छेरी बैंक' जैसा नयाचार भी महिलाओं को पशुपालन आधारित आजीविका से जोड़ रहा है। 'लखपति दीदी' आय का आँकड़ा भर नहीं, निर्भरता से आत्मनिर्भरता और संकोच से आत्मविश्वास तक की रास्ता का प्रतीक है।

पशुपालन व खेती से मजबूत होती ग्रामीण अर्थव्यवस्था

वैज्ञानिक तकनीक, नस्ल सुधार और विभागीय मार्गदर्शन से पशुपालन आय का मजबूत जरिया बन रहा है। सीतापुर के दयासागर ने पशुपालन विभाग की सलाह पर कृत्रिम गर्भाधान से नस्ल सुधारी, जिससे दुग्ध उत्पादन बढ़ा और निरमित आय का आधार बना। लुण्ठा के जगनाथ राम ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन की मदद से दूधरी पालन को आजीविका बनाया। खेती में भी बदलाव दिख रहा है। सरगुजा में सीर मुजला योजना से किसानों को सीर सिंचाई पंप मिले हैं। लबेद सिंह जैसे किसान अब धान के साथ दलहन, तिलहन, सब्जियाँ, फलदार पौधे और फूलों की खेती कर रहे हैं। इबरी के जरिए मछली पालन जैसी गतिविधियाँ आय का अतिरिक्त स्रोत बन रही हैं। मृदा परीक्षण और जल संरक्षण संरचनाएँ खेती को अधिक वैज्ञानिक और लाभकारी बना रही हैं।

युवाओं पर दांव, उच्च शिक्षा में मिशन मोड

प्रदेश के विकास मॉडल के केंद्र में "GYAN" है, रानी ग्रीब, युवा, अन्नदाता और नारी। युवाओं के लिए उच्च शिक्षा में व्यापक बदलाव की शुरुआत हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) के किराचन्द्रन में विभाग मिशन मोड में है। प्रदेश का सकल नामांकन अनुपात 2021-22 के 19.6 प्रतिशत से बढ़कर 27.5 प्रतिशत हो गया है, और 2035 तक इसे 50 प्रतिशत करने का लक्ष्य है। हर जिले में एक 'सेटर ऑफ एक्सीलेंस' महाविद्यालय बनाया जा रहा है। पात्र 254 शासकीय महाविद्यालयों में से 200 और 9 में से 5 विश्वविद्यालयों का नेक मूल्यांकन पूरा हो चुका है। वर्ष 2025-26 में 8 नए शासकीय महाविद्यालय, 5 नए निजी महाविद्यालय और 3 नए निजी विश्वविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं।





निकाय चुनाव की नई बिसात

भिलाई से रिसाली तक आरक्षण से बदले समीकरण और
वार्ड की समस्याओं के बीच भाजपा-कांग्रेस की अगली परीक्षा

भि लाई-दुर्ग अंचल में नगरीय निकाय चुनाव की आहट अब राजनीतिक गतिविधियों को धीरे-धीरे चुनावी मोड़ में ले जा रही है। चुनाव की औपचारिक तारीख भले अभी सामने नहीं आई हो, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर तैयारी आगे बढ़ चुकी है और दिसंबर 2026 में कार्यकाल पूरा होने वाले नगर निगमों में भिलाई, रिसाली और भिलाई-चरोदा शामिल है। तीनों निगमों के वार्डों का आरक्षण भी पूरा हो चुका है। इसके साथ ही संभावित प्रत्याशियों की तस्वीर, पुराने दावेदारों की चिंता और नए चेहरों की उम्मीद का दौर शुरू हो गया है। राजनीतिक रूप से यह चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां मुकाबला केवल भाजपा और कांग्रेस के चुनाव चिह्नों के बीच नहीं होगा। हर वार्ड में स्थानीय संगठन, प्रत्याशी की व्यक्तिगत पकड़, पिछले पांच साल का निगम अनुभव, बुनियादी सुविधाओं की स्थिति और

बड़े नेताओं का प्रभाव एक साथ काम करेगा। विधानसभा या लोकसभा चुनाव के मुकाबले निकाय चुनाव में मतदाता का मुह अधिक स्थानीय होता है। सड़क पर पानी भर रहा है या नहीं, नाली साफ होती है या नहीं, कचरा समय पर उठता है या नहीं, स्ट्रीट लाइट जलती है या नहीं और निगम कार्यालय में काम कितनी आसानी से होता है, ये सबाल बड़े राजनीतिक नारों पर भारी पड़ सकते हैं।

भाजपा ने संगठन को पहले चुनावी मैदान में उतारा

भाजपा ने तीनों निगमों में चुनावी जिम्मेदारियां तय करके अपनी संगठनात्मक तैयारी का संकेत दे दिया है। भिलाई नगर निगम की जिम्मेदारी भूपेंद्र सवत्री को, रिसाली की जिम्मेदारी अनुराग सिंहदेव को और भिलाई-चरोदा की जिम्मेदारी नीलू शर्मा को दी गई है। भिलाई के लिए लक्ष्मी

वर्मा और चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी तथा रिसाली के लिए श्वेता शर्मा और आसू चंद्रवंशी को सहप्रभारी बनाए जाने की भी सूचना सामने आई है। इसके बाद भिलाई के 70 वार्डों को लेकर संगठनात्मक बैठकों का दौर चला है। वृथ समितियों को सक्रिय करने, मतदाता सूची का अध्ययन करने और कार्यकर्ताओं के जनसंपर्क पर जोर दिया गया है। इसका राजनीतिक अर्थ इतना ही है कि भाजपा ने चुनाव को केवल टिकट घोषणा के बाद शुरू होने वाला अभियान नहीं माना है। संगठन को पहले सक्रिय करने की कोशिश दिखाई दे रही है। लेकिन इस सक्रियता की वास्तविक परीक्षा तब होगी जब टिकट के दावेदारों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। संगठन की पसंद, स्थानीय स्वीकार्यता और बड़े नेताओं के प्रभाव के बीच संतुलन बनाना हर दल के लिए चुनौती रहेगा। भाजपा जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम देवागन ने भी कहा है कि पार्टी में संगठन सर्वोपरि है। दूसरी तरफ कांग्रेस जिला अध्यक्ष

मुकुंश चंद्राकर के अनुसार निगम चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं और पांच अक्टूबर को बैठक प्रस्तावित है। उनका कहना है कि संगठन की तय प्रक्रिया के तहत वार्डों में प्रत्याशी चयन किया जाएगा। इसलिए कांग्रेस को पूरी तरह निष्क्रिय बताना सही नहीं होगा। उसकी गतिविधि का स्वरूप फिलहाल भाजपा की तरह व्यापक वृद्ध-केंद्रित तैयारी के रूप में उतना स्पष्ट दिखाई नहीं देता। यही अंतर आने वाले समय में राजनीतिक चर्चा का विषय बन सकता है।

कांग्रेस के सामने चुनौती, आंदोलन से चुनावी संगठन तक पहुंचने की

कांग्रेस स्थानीय और सरकार विरोधी मुद्दों को लेकर सक्रिय है, लेकिन नगर निगम चुनाव की अपनी अलग कार्यशैली होती है। विधानसभा चुनाव में राज्य सरकार के कामकाज, बड़े राजनीतिक मुद्दे और नेतृत्व की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। निकाय चुनाव में वार्ड का पार्षद ही मतदाता के सामने सबसे पहले जवाबदेह दिखाई देता है। इसलिए कांग्रेस के सामने दोहरी चुनौती होगी। पहली, अपने मौजूदा संगठन और निर्वाचित पार्षदों के बीच तालमेल बनाए रखना। दूसरी, उन वार्डों में नए चेहरों की तलाश करना जहां आरक्षण बदलने के कारण पुराने दावेदार चुनावी दौड़ से बाहर हो गए हैं। कांग्रेस ने तीनों निगमों के लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए हैं। भिलाई के लिए धनेन्द्र साहू, रिसाली के लिए मोहन मरकाम और भिलाई-चरोदा के लिए विकास उपाध्याय को पर्यवेक्षक बनाए जाने की जानकारी सामने आई है। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस की चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, भले ही उसका सार्वजनिक संगठनात्मक अभियान भाजपा की तुलना में अभी कम दिखाई दे रहा हो। यहां कांग्रेस के सामने एक और सवाल है। वह अपने मौजूदा पार्षदों के कामकाज को टिकट का आधार बनाएगी या वार्ड की नई राजनीतिक जरूरतों को प्राथमिकता देगी? यदि संगठन स्थानीय कार्यकर्ताओं और संभावित प्रत्याशियों के बीच समय रहते समन्वय बना लेता है तो टिकट की अंदरूनी प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित करना आसान हो सकता है। लेकिन यदि दावेदारी बड़े नेताओं की पसंद और स्थानीय गुटबाजी के बीच उलझी, तो उसका असर चुनावी अभियान पर भी पड़ सकता है।

भिलाई में 70 वार्ड, महापौर पद का आरक्षण और टिकट की सबसे बड़ी परीक्षा

भिलाई नगर निगम तीनों में सबसे बड़ा राजनीतिक मैदान है। यहां 70 वार्ड हैं और महापौर पद अन्ध पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। नौ सितंबर को वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब अनेक संभावित प्रत्याशियों की रणनीति बदल गई है। आरक्षण ने टिकट की राजनीति को नई दिशा दी है। जिस चेहरे को सामान्य वार्ड से लड़ने की उम्मीद थी, उसका वार्ड किसी आरक्षित वर्ग में जा सकता है। दूसरी ओर ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए रास्ता खुल सकता है, जो पहले टिकट की दौड़ में पीछे माने जा रहे थे। यही वजह है कि भिलाई में सबसे बड़ा सवाल केवल यह नहीं है कि किस पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा। सवाल यह भी है कि दोनों दल वार्ड स्तर पर संगठन और व्यक्तिगत लोकप्रियता के बीच किस तरह तालमेल बैठालेंगे। महापौर पद का औबीसी आरक्षण भी राजनीतिक रणनीति को प्रभावित करेगा। महापौर के संभावित चेहरों की चर्चा अब केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का विषय नहीं रहेगी। पार्टी को यह देखना होगा कि महापौर पद के लिए सामने आने वाला चेहरा अलग-अलग सामाजिक और भौगोलिक हिस्सों में कितनी स्वीकार्यता रखता है।

टिकट की दौड़ में संगठन बनाम प्रभाव का सवाल

70 वार्डों में टिकट के दावेदार सक्रिय होना स्वाभाविक है। पार्षद का चुनाव स्थानीय राजनीति में आगे बढ़ने का पहला बड़ा रास्ता भी माना जाता है। इसलिए टिकट के लिए संगठन के सामने दावेदारी के साथ-साथ व्यक्तिगत संपर्कों का दौर भी चलना शुरू हो गया है। दोनों दलों में एक ही सवाल अलग-अलग रूप में मौजूद है। टिकट संगठन की प्रक्रिया से तय होगा या बड़े नेताओं की पसंद भी प्रभाव डालेगी? भाजपा ने संगठन सर्वोपरि होने की बात कही है। कांग्रेस भी पार्षदों और बैठकों के जरिए प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात कर रही है। लेकिन अंतिम परीक्षा तब होगी जब एक वार्ड से कई दावेदार सामने होंगे। सर्वे और फीडबैक की चर्चा भी इसी वजह से महत्वपूर्ण है। निकाय चुनाव में केवल पार्टी के प्रति निष्ठा पर्याप्त नहीं होती। प्रत्याशी वार्ड वार्ड में मौजूदगी, सामाजिक संबंध, स्थानीय समस्याओं की समझ और चुनावी दिन कार्यकर्ताओं को साथ रखने की क्षमता भी महत्वपूर्ण होती है। यही कारण है कि इस चुनाव में कई नए चेहरे पुराने नेताओं के राजनीतिक प्रभाव को चुनौती दे सकते हैं, जबकि पुराने स्थानीय चेहरे अपने व्यक्तिगत नेटवर्क के आधार पर टिकट के लिए मजबूत दावा पेश कर सकते हैं।



रिसाली में ताम्रध्वज साहू बनाम ललित चंद्राकर की चर्चा से आगे की राजनीति

रिसाली नगर निगम का समीकरण तीनों निगमों में अलग प्रकृति का है। निगम में 40 वार्ड हैं और महापौर पद अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित किया गया है। वार्ड आरक्षण के बाद अब दोनों प्रमुख दलों को नए सामाजिक समीकरणों के अनुसार चेहरे तलाशने होंगे। रिसाली की राजनीति में पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और दुर्गा ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर के नामों को लेकर चर्चा स्वाभाविक है। विधानसभा चुनाव में दोनों अलग राजनीतिक खेमों से आमने-सामने रहे थे। निगम चुनाव में भी उनके प्रभाव वाले राजनीतिक समूहों की गतिविधियों पर नजर रहेगी। लेकिन रिसाली का चुनाव केवल दो नेताओं के बीच मुकाबले के रूप में देखना अट्ठा होगा। यहाँ 40 वार्डों की अपनी अलग राजनीति है। वर्तमान में निगम में कांग्रेस के पास बहुमत की स्थिति रही है, जबकि विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भाजपा विधायक के पास है। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार पिछले निगम चुनाव में कांग्रेस ने 21, भाजपा ने 12 और निर्दलीयों ने सात वार्ड जीते थे। अब आरक्षण की नई तस्वीर ने पुराने समीकरणों को भी प्रभावित किया है। महापौर पद अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित होने से दोनों दलों के सामने एक नए चेहरे को आगे लाने की जरूरत होगी। इसलिए रिसाली में बड़े नेताओं का प्रभाव महत्वपूर्ण जरूर रहेगा, लेकिन टिकट का अंतिम असर वार्ड स्तर की स्वीकारता पर भी निर्भर करेगा।

पानी, सीवरेंज और जमीन का सवाल रिसाली की राजनीति का केंद्र

रिसाली के चुनाव में बुनियादी सुविधाएँ सबसे स्वाभाविक राजनीतिक मुद्दे बन सकती हैं। पानी की आपूर्ति, सीवरेंज, सफाई, खाली प्लॉटों में कचरा और जमीन से जुड़े प्रशासनिक विषय स्थानीय नागरिकों के सीधे अनुभव से जुड़े हैं। बीएसपी की जमीन और एनओसी से जुड़ी निर्भरता भी विकास कार्यों की चर्चा में आती रही है। पार्क, सामुदायिक भवन और सड़क चौड़ीकरण जैसे कार्यों में जमीन की उपलब्धता और अनुमति का सवाल महत्वपूर्ण हो सकता है। रिसाली, तालपुरी, मरोदा और रुआबाड़ा जैसे इलाकों में पानी की समस्या और सीवरेंज से जुड़ी शिकायतों को लेकर राजनीतिक दलों के पास एक तैयार स्थानीय मुद्दा मौजूद है। चुनाव में कौन सा दल इन समस्याओं को ठोस समाधान की योजना के साथ मतदाता के सामने रखता है, यह उसके स्थानीय अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। पट्टा और नियमितकरण भी कई इलाकों में राजनीतिक चर्चा के विषय रहे हैं। निकाश चुनाव की खासियत यही है कि जिस समस्या का असर योजना की ज़िंदगी पर पड़ता है, वहीं समस्या राजनीतिक बहस का सबसे मजबूत आधार बन सकती है।

भिलाई-चरोदा में अलग भूगोल, अलग राजनीतिक भाषा

भिलाई-चरोदा को भिलाई के साथ रखकर देखना राजनीतिक रूप से आसान है, लेकिन यहाँ की जमीन अलग है। 40 वार्ड वाले इस निगम में आरक्षण प्रक्रिया के बाद 14 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हुए हैं। भिलाई-चरोदा की राजनीति में ग्रामीण से शहरी संक्रमण, पुरानी बस्तियाँ, सड़क, नाली, जल निकासी, स्ट्रीट लाइट, सफाई और विकास कार्यों को पहुँच जैसे सवाल महत्वपूर्ण रह सकते हैं। पिछले निगम चुनाव में कांग्रेस ने 19, भाजपा ने 14 और निर्दलीयों ने सात वार्ड जीते थे। इससे पता चलता है कि दोनों प्रमुख दलों के बीच स्थानीय स्तर पर मुकाबला पहले से मौजूद रहा है और निर्दलीय भी समीकरण प्रभावित करने की स्थिति में रहे हैं। आरक्षण के बाद कई पुराने राजनीतिक चेहरों की स्थिति बदल गई है। इसलिए इस बार पार्टी को केवल पुराने पार्षदों पर निर्भर रहने के बजाय वार्ड की नई सामाजिक संरचना के अनुरूप चेहरे तलाशने होंगे। भिलाई-चरोदा की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जुड़ा राजनीतिक संदर्भ भी चर्चा में आता रहा है। लेकिन निकाश चुनाव में किसी बड़े नेता का प्रभाव तभी स्थानीय सीट में बदलता है जब वार्ड स्तर का संगठन, प्रत्याशी और बूथ प्रबंधन उसके साथ खड़ा हो।

आरक्षण ने बदल दिया तीनों निगमों का टिकट गणित

नौ सितंबर की आरक्षण प्रक्रिया के बाद अब तीनों निगमों में टिकट की राजनीति पहले से अधिक जटिल हो गई है। भिलाई में 70 वार्ड, रिसाली में 40 और भिलाई-चरोदा में 40 वार्ड हैं। महापौर पद भी अलग-अलग सामाजिक श्रेणियों के लिए आरक्षित है। इसका सीधा असर यह होगा कि कई पुराने पार्षद अपने मौजूदा वार्ड से चुनाव नहीं लड़ पाएँगे। कुछ को दूसरे वार्ड में जमीन तलाशनी होगी, कुछ नए चेहरे सामने आएँगे और कुछ संगठन में दूसरी भूमिका तलाश सकते हैं। महिलाओं की भूमिका भी इस चुनाव में महत्वपूर्ण होगी। वार्ड आरक्षण के साथ महापौर पदों का आरक्षण राजनीतिक दलों को महिला नेतृत्व के नए चेहरे सामने लाने का अवसर देता है। यहाँ टिकट चयन केवल जातीय या सामाजिक समीकरण तक सीमित नहीं रहेगा। पार्टी को जीतने योग्य स्थानीय संगठन, कार्यकर्ता नेटवर्क, मतदाता संपर्क और उम्मीदवार की सार्वजनिक छवि जैसे कई पहलुओं को साथ लेकर चलना होगा।

बड़े नेताओं की छाया में स्थानीय चेहरे कितने मजबूत?

निकाश चुनाव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बड़े नेता चुनाव का माहौल बना सकते हैं, लेकिन हर वार्ड में चुनाव लड़ने वाला चेहरा अलग होता है। भिलाई में औद्योगिक टाउनशिप और श्रमिक बस्तियों की समस्याएँ अलग हैं। रिसाली में नई बस्तियाँ, पानी और सीवरेंज के सवाल अलग हैं। भिलाई-चरोदा में ग्रामीण पृष्ठभूमि से शहरी विस्तार तक की समस्याएँ अलग हैं। इसलिए तीनों निगमों के लिए एक ही चुनावी नारा या एक ही रणनीति पर्याप्त नहीं होगी। पार्टी नेतृत्व को स्थानीय मुद्दों के हिसाब से अलग-अलग अभियान तैयार करना होगा। भाजपा के सामने संगठनात्मक तैयारी को टिकट वितरण तक ले जाने की चुनौती होगी। कांग्रेस के सामने अपने मौजूदा स्थानीय आधार, पार्षदों और नए दावेदारों को एक साथ सराने की चुनौती होगी।



भिलाई नगर निगम

कुल वार्ड : 70

ओबीसी 23

सामान्य (संख्या तय)

अनुसूचित जाति (संख्या तय)

अनुसूचित जनजाति (संख्या तय)



**महापौर पद
ओबीसी के लिए आरक्षित**

रिसाली नगर निगम

कुल वार्ड : 40



**महापौर पद
अनुसूचित जाति महिला
के लिए आरक्षित**

**40 वार्डों के आरक्षण ने भी
पुराने चेहरों के सामने
नई चुनौती खड़ी कर दी है।**

भिलाई-चरोदा नगर निगम

कुल वार्ड : 40

**महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड 14
(40 में से)**

वार्ड की जाली से लेकर महापौर की कुर्सी तक

इन चुनावों में राज्य और राष्ट्रीय राजनीति की छाया जरूर रहेगी। विधानसभा और लोकसभा के राजनीतिक प्रभाव भी मतदाताओं की सोच पर असर डाल सकते हैं। लेकिन नगर निगम का चुनाव अंततः नागरिक सुविधाओं के सबसे नजदीक होता है। एक परिवार के लिए पानी की समस्या किसी बड़े राजनीतिक भाषण से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। किसी बाजार क्षेत्र के लिए पाकिंग और अतिक्रमण बड़ा सवाल हो सकता है। किसी बस्ती के लिए सड़क और जाली चुनाव का मुख्य मुद्दा हो सकता है। किसी टाउनशिप क्षेत्र में सड़क, सफाई, प्रकाश व्यवस्था या सार्वजनिक सुविधाएं ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती हैं। यही वजह है कि चुनाव का वास्तविक राजनीतिक मैदान वार्डों में तैयार होगा।

अब अगली लड़ाई टिकट और संगठन की

भाजपा ने प्रभारी नियुक्त करके चुनावी संगठन को सक्रिय करने का कदम उठा लिया है। भिलाई में 70 वार्डों के बूथ स्तर तक तैयारी की गतिविधियां सामने आ चुकी हैं। कांग्रेस ने भी पर्यवेक्षक नियुक्त कर प्रक्रिया शुरू कर दी है और वार्ड स्तर पर प्रत्याशी चयन की तैयारी की बात कही है। अब दोनों दलों के सामने असली चुनौती अपने-अपने दावेदारों को संभालने की है। क्योंकि चुनाव में केवल उम्मीदवार घोषित करना पर्याप्त नहीं होगा। टिकट न मिलने वाले दावेदारों को साथ रखना, वार्ड संगठन को एकजुट रखना, निर्दलीय बगलत को संभालना को नियंत्रित करना और मतदाता तक स्थानीय मुद्दों के साथ पहुंचना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। तीनों निगमों की राजनीतिक तस्वीर इसलिए एक जैसी नहीं है। भिलाई में 70 वार्डों का बड़ा संगठनात्मक विस्तार है। रिसाली में 40 वार्डों के साथ सत्ता और विचारों के अलग-अलग दलों में होने का समीकरण है। भिलाई-चरोदा में स्थानीय सामाजिक संरचना और पुराने राजनीतिक प्रभावों का अपना महत्व है। इस लिहाज से दिसंबर के प्रस्तावित चुनाव की असली कहानी अभी उम्मीदवारों के नाम आने से पहले लिखी जा रही है। एक तरफ संगठन अपने बूथ और वार्ड मजबूत कर रहे हैं, दूसरी तरफ दावेदार अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। आरक्षण ने पुराने समीकरणों को बदला है और स्थानीय मुद्दों ने चुनाव का एजेंडा तैयार करना शुरू कर दिया है। आविरोकार भिलाई, रिसाली और भिलाई-चरोदा के मतदाता अपने वार्ड में किसे चुनते हैं, वह कई स्तरों के समीकरणों पर निर्भर करेगा। लेकिन इतना स्पष्ट है कि इस बार चुनावी मुकाबला केवल बड़े नेताओं की सभाओं से तय नहीं होगा। असली परीक्षा उस प्रत्याशी और उस संगठन की होगी, जो वार्ड की रोजमर्रा की समस्याओं को सबसे स्पष्ट तरीके से समझकर मतदाता के दरवाजे तक पहुंच पाए।





सेप्टिक टैंक का राज!

लिव-इन पार्टनर की हत्या कर लाश घर के पीछे बने सेप्टिक टैंक में छिपाया

को रबा जिले के छोटे से गांव बरपाली में उस सुबह सब कुछ सामान्य जैसा ही था। लेकिन मनोज उरांव के घर के पीछे बनी बाड़ी में कुछ ऐसा था, जिसकी मौजूदगी से किसी को अंदाजा तक नहीं था कि एक महिला की मौत का राज जमीन के नीचे दबा पड़ा है। सेप्टिक टैंक का बकून पूरी तरह बंद नहीं था। वह आधा खुला हुआ था। पास पहुंचते ही हवा में एक तेज और असहनीय दुर्गंध महसूस हो रही थी। संतोषी के भाई रामभरोस और परिवार के दूसरे लोगों के कदम वहीं ठिठक गए। कई दिनों से वे अपनी बहन को खोज रहे थे। रक्षाबंधन के दिन वह घर नहीं आई थी।

मनोज से पूछा गया था तो उसने कहा था कि संतोषी एक दिन पहले ही कहीं चली गई है। लेकिन अब सामने कुछ और ही कहानी खड़ी थी। दुर्गंध उसी सेप्टिक टैंक से आ रही थी। क्या संतोषी के गायब होने का राज इसी टैंक के भीतर छिपा था? परिजनों ने पुलिस को खबर कर दी। कुछ ही देर बाद रवांग घाना प्रभारी लक्ष्मण खूटे पुलिस टीम के साथ वहां पहुंच गए। घटनास्थल देखा गया। मामला गंभीर था, इसलिए वरिष्ठ अधिकारियों और कार्यपालिक दंडाधिकारी को सूचना दी गई। सुबह कार्यपालिक दंडाधिकारी की मौजूदगी में सेप्टिक टैंक खोला गया। बकून हटते ही भीतर

जो दिखाई दिया, उसने वहां मौजूद लोगों को स्तब्ध कर दिया। टैंक के भीतर एक महिला की सड़ी-गली लाश पड़ी थी। परिजनों ने उसकी पहचान 33 साल की संतोषी के रूप में की। जिस बहन के हाथों से रक्षाबंधन पर राखी बंधने का इंतजार था, उसका शव उसी घर के पीछे एक सेप्टिक टैंक से बरामद हुआ था। लेकिन यह कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। इसका असली सिरा करीब दो साल पहले जुड़ता है। और फिर 27 अगस्त की उस रात तक पहुंचता है, जब एक घरेलू विवाद ने ऐसा मोड़ लिया, जिसकी परतें अब पुलिस जांच में खुल रही हैं।

यह मामला छत्तीसगढ़ के कोरवा जिले के रवांग घाना क्षेत्र के ग्राम बरपाली का है। पुलिस के मुताबिक, संतोषी करीब दो साल से 40 वर्षीय मनोज उरांव के साथ लिव-इन में रह रही थी। मनोज पर आरोप है कि 27 अगस्त को किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद उसने संतोषी के साथ मारपीट की। आसपास के लोगों ने बीच-बचाव कर उस समय मामला शांत करा दिया था, लेकिन आरोप है कि देर शाम मनोज ने फिर संतोषी की पिटाई की, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इसके बाद शव को घर के पीछे बने सेप्टिक टैंक में डालकर बकून बंद कर दिया गया। घटना के बाद मनोज फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

27 अगस्त की रात हुआ था विवाद

संतोषी की जिंदगी का कलनी भी कई मोड़ से लेकर गुजरी थी। वर्ष 2001 में उसकी शादी कपतला क्षेत्र में हुई थी और उसके चार बच्चे हैं। करीब 15 साल पहले उसके पति की मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद संतोषी अपने ससुराल में रह रही थी। इसी दौरान करीब दो साल पहले उसकी जिंदगी में मनोज उरांव आया और वह उसके साथ लिव-इन में रहने लगी। मनोज की पत्नी की भी मौत हो चुकी है। दोनों बरपाली में साथ रह रहे थे। पुलिस के मुताबिक, मनोज नशे का आदी बताया जा रहा है और दोनों के बीच किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता रहता था। 27 अगस्त को भी कुछ ऐसा ही हुआ। बताया जा रहा है कि मनोज के साथ विवाद के दौरान संतोषी के साथ मारपीट हुई। आसपास के लोगों को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने बीच-बचाव कर दोनों को अलग किया और मामला शांत करा दिया। लेकिन उस समय शांत हुआ विवाद देर शाम फिर भड़क गया। आरोप है कि मनोज ने दोबारा संतोषी को पिटाई की और इसके बाद उसकी मौत हो गई। इसके बाद जो हुआ, उसने इस मामले को और गंभीर बना दिया। आरोप है कि संतोषी की मौत के बाद मनोज ने शव को घर के पीछे बने सेप्टिक टैंक में डाल दिया और उसका बकून बंद कर दिया। इसके बाद घर में ऐसी खामोशी छा गई, जिसके भीतर एक मौत का राज दबा था। दूसरी तरफ संतोषी के मारके वालों को इस बात की भनक तक नहीं दी कि उनके अपने परिवार की महिला के साथ क्या हो चुका है।

रक्षाबंधन पर नहीं आई तो भाइयों को हुई चिंता

घटना के अगले दिन रक्षाबंधन था। संतोषी के भाई अपनी बहन का इंतजार कर रहे थे। लेकिन वह मायके नहीं पहुंची। शुरुआत में परिजनों को लगा कि शायद किसी वजह से वह नहीं आ सकी होगी, लेकिन जब उसके आने की कोई खबर नहीं मिली तो भाइयों ने मनोज से संपर्क किया और संतोषी के बारे में पूछा। मनोज ने उन्हें बताया कि संतोषी एक दिन पहले ही कहीं चली गई है। यह जवाब उस समय शायद एक सामान्य सफाई जैसा लगा हो, लेकिन संतोषी के कई दिन तक वापस नहीं लौटने के बाद यही बात परिजनों के लिए सवाल बन गई। आखिर वह कहाँ गई थी? अगर वह घर से चली गई थी तो अब तक लौटकर क्यों नहीं आई? उसने परिवार से संपर्क क्यों नहीं किया? भाइयों को कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा था। दिन गुजरते गए, लेकिन संतोषी का कोई पता नहीं चला। धीरे-धीरे परिवार की चिंता बढ़ती गई और उन्होंने उसकी तलाश शुरू कर दी। तलाश के दौरान मनोज के बताए जाने पर भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। परिवार को उसके व्यवहार और जवाबों पर संदेह होने लगा था।

कत्ल की रात की कड़ियां जोड़ रही पुलिस

पुलिस के मुताबिक, मनोज ने संतोषी के साथ मारपीट की थी और आसपास के लोगों ने बीच-बचाव करके मामला शांत कराया था। आरोप है कि देर शाम उसने दोबारा संतोषी की पिटाई की, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इसके बाद शव को सेंट्रिक टैंक में छिपाने की बात सामने आई है। अब पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ रही है। विवाद किस बात को लेकर शुरू हुआ था? मारपीट किस तरह हुई? आसपास के लोगों ने पहली बार जब बीच-बचाव किया, तब संतोषी की हालत कैसी थी? देर शाम दोबारा क्या हुआ? उसकी मौत कब हुई और इसके बाद शव को सेंट्रिक टैंक में कैसे डाला गया? इन सभी सवालों के जवाब पुलिस की जांच में तलाश जा रहे हैं। मौत के वास्तविक कारण की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही होगी। पुलिस शव की जांच, पोस्टमार्टम और घटनास्थल से मिलने वाले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक एक्सपर्ट और मेडिकल कॉलेज की टीम भी मौके पर पहुंची। शव की स्थिति खराब होने के कारण वैज्ञानिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस मामले में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पुलिस अब उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह पता लगाने में जुटी है कि संतोषी की मौत किन परिस्थितियों में हुई। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि शव को सेंट्रिक टैंक में छिपाने के पीछे क्या परिस्थितियां थीं और घटना के बाद मनोज की भूमिका क्या रही। फिलहाल मनोज उरांव फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।



22 दिन बाद मिली लाश

कई दिन तक संतोषी की कोई जानकारी नहीं मिलने के बाद 19 सितंबर को उसका भाई रामभरोस और परिवार के अन्य लोग मनोज के घर पहुंचे। इस बार परिजन सिर्फ संतोषी के बारे में पूछने नहीं आए थे, बल्कि उसकी तलाश कर रहे थे। घर के भीतर और आसपास नजर दौड़ाने के बाद जब वे पीछे की ओर बाड़ी में पहुंचे तो उनकी नजर सेंट्रिक टैंक पर पड़ी। टैंक का ढक्कन आधा खुला था। वहाँ से मामला अचानक एक अलग दिशा में मुड़ गया। टैंक के भीतर से तेज बदबू आ रही थी। इतनी तेज कि वहां खड़े लोगों का संदेह और गहरा गया। कई दिनों से गायब संतोषी और घर के पीछे आधा खुला सेंट्रिक टैंक, दोनों बातें एक-दूसरे से जुड़ी नजर आने लगीं। परिजनों ने किसी तरह का जोखिम नहीं लिया और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही श्याम धाना प्रमोटी लक्ष्मण चूटे पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों और कार्यालयिक दंडाधिकारी को भी सूचना दी गई। अगले दिन सुबह कार्यालयिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सेंट्रिक टैंक खोलने की कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में जब टैंक का ढक्कन हटाया गया तो अंदर एक सड़ी-गली लाश दिखाई दी। शव को बाहर निकालवाया गया। परिजनों ने उसकी पहचान संतोषी के रूप में की। जिस महिला की तलाश उसके भाई कई दिनों से कर रहे थे, वह उनके सामने मृत पड़ी थी। जिस रक्षाबंधन पर उसके भाइयों को उसकी कलाई पर राखी बंधवानी थी, उसी त्योहार के बाद शुरू हुई तलाश आधिकारिक उसकी लाश तक पहुंच गई थी। पुलिस ने शव का पंचनामा कराया और मांग कायम कर जांच शुरू कर दी। मामला अब सिर्फ संतोषी के लापता होने का नहीं था। पुलिस के सामने उसकी मौत की पूरी कहानी सामने लाने की चुनौती थी।

एक गुमशुदगी ने खोला मौत का राज

इस पूरी घटना में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी रक्षाबंधन का वह दिन बना, जब संतोषी अपने भाइयों के घर नहीं पहुंची। अगर वह उस दिन मायके पहुंच जाती तो शायद परिवार को उसकी स्थिति के बारे में कुछ और जानकारी मिलती। लेकिन उसके नहीं आने पर भाइयों ने मनोज से पूछताछ की। मनोज ने बताया कि संतोषी एक दिन पहले ही कहीं चली गई है। वही जवाब बाद में परिवार के लिए संदेह की वजह बन गया। संतोषी का कई दिनों तक कोई पता नहीं चला तो तलाश शुरू हुई। 19 सितंबर को रामभरोस और अन्य परिजन मनोज के घर पहुंचे। घर के पीछे गए तो सेंट्रिक टैंक का ढक्कन आधा खुला मिला। भीतर से उठ रही तेज बदबू ने संदेह को और मजबूत कर दिया। पुलिस को बुलाया गया और अगले दिन टैंक खोला गया। अंदर से संतोषी की सड़ी-गली लाश मिली। अब इस मामले में एक महिला की मौत, लिव-इन पार्टनर पर हत्या का आरोप, शव को सेंट्रिक टैंक में छिपाने का आरोप और आरोपी का फरार होना, ये सभी कड़ियां पुलिस की जांच का हिस्सा हैं। संतोषी के जीवन का अंत 27 अगस्त की उस रात कैसे हुआ, यह सवाल अभी जांच के केंद्र में है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच और अन्य साक्ष्यों के अभाव पर आगे बढ़ रही है। मनोज उरांव की गिरफ्तारी के बाद ही इस मामले से जुड़े कई सवालों के जवाब सामने आने की उम्मीद है। फिलहाल बरपाली में उस घर के पीछे मौजूद सेंट्रिक टैंक की कहानी हर किसी को विचलित कर रही है। जिस टैंक को लोग रोजमर्रा की जिंदगी का एक सामान्य हिस्सा समझते थे, उसी के भीतर कई दिनों तक एक महिला की लाश छिपी रही। परिवार अपनी बहन को तलाशता रहा और आरोपी के बताए अनुसार उसके कहीं चले जाने की बात पर जवाब खोजता रहा। लेकिन अंत में सब किसी बयान से नहीं, बल्कि उस तैज दुर्घटना से सामने आया, जिसे ज्यादा दिनों तक दबाकर रखना संभव नहीं था। रक्षाबंधन पर बहन का इंतजार कर रहे भाइयों की तलाश आधिकारिक उस जगह जाकर घट्ना हुई, जहां संतोषी की जिंदगी का राज भी दफन था।

नशा मुक्त भारत के लिए राज्यपाल डेका की पदयात्रा



रायपुर में सेवा संकल्प अभियान के तहत नशा मुक्त भारत के संकल्प के साथ पदयात्रा आयोजित की गई। राज्यपाल रमन डेका पदयात्रा में शामिल हुए और नागरिकों को नशामुक्त समाज के निर्माण का संदेश दिया। राज्यपाल ने टाउन हॉल से शुरू हुई पदयात्रा में सहभागिता की। पदयात्रा के दौरान भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादूर शास्त्री की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। टाउन हॉल रायपुर से प्रारंभ होकर पदयात्रा अंबेडकर चौक पहुंची, जहां राज्यपाल रमन डेका ने 'भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने नशामुक्त भारत के निर्माण के लिए सामूहिक सहभागिता और जनजागरूकता को महत्वपूर्ण बताया। पदयात्रा में सांसद दुर्जमोहन अग्रवाल, विधायक पुरंदर मिश्रा, सुनील सोनी सहित बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं, विद्यार्थी और शहर के नागरिक शामिल हुए। पदयात्रा के दौरान प्रतिभागियों ने नशे से दूर रहने और समाज को नशामुक्त बनाने का संकल्प लिया।

अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों का सम्मान



उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने बिलासपुर के बहतराई स्थित खेलो इंडिया उत्कृष्टता केंद्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतकर छत्तीसगढ़ और देश का गौरव बढ़ाने वाली खिलाड़ियों के सम्मान किया। उन्होंने एशियन गेम्स-2026 में कबड्डी की स्वर्ण पदक विजेता संजू देवी तथा जूनियर हाकी एशिया कप-2026 की स्वर्ण पदक विजेता मधु सिदार और गीता यादव को सम्मानित किया। समारोह की अध्यक्षता बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने की। समारोह में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा सुश्री संजू देवी के लिए पूर्व में घोषित 51 लाख रुपए की सम्मान राशि का चेक प्रदान किया गया। वहीं मधु सिदार और गीता यादव को 11 लाख 12 हजार रुपए प्रत्येक की विशेष सहायता पैकेज देने की घोषणा की गई। कार्यक्रम में दोनों को इसमें से तत्काल 2-2 लाख रुपए की एकमुश्त सहायता राशि के चेक प्रदान किए गए। अरुण साव ने तीनों खिलाड़ियों को शाल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।

शिक्षा मंत्री ने स्कूलों में साईंशयोर न्यूट्रिशन पायलट प्रोजेक्ट का किया शुभारंभ



प्रदेश के शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए श्री सत्य साईं अन्नपूर्णा ट्रस्ट के सहयोग से छत्तीसगढ़ में "साईंशयोर न्यूट्रिशन कार्यक्रम" के पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। रायपुर जिले के तीन शासकीय विद्यालयों से शुरू किए गए इस कार्यक्रम के प्रथम घरण में लगभग 500 बच्चों को नि:शुल्क पोषण सहयोग प्रदान किया जाएगा। इस मौके पर श्री सत्य साईं अन्नपूर्णा ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री आनंद कडली, शिक्षा विभाग के अधिकारी, विद्यालयों के शिक्षक, श्री सत्य साईं संजीवनी अस्पताल की टीम सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। अतिथियों ने बच्चों को साईंशयोर न्यूट्रिशन का वितरण कर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की।

रायगढ़ में ओपन जिम और आंगनवाड़ी भवन का शिलान्यास



वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओ.पी. चौधरी ने रायगढ़ नगर निगम के वार्ड क्रमांक 33 में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उन्होंने ओपन जिम और आंगनवाड़ी भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास तथा नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि रायगढ़ के प्रत्येक वार्ड में नागरिक सुविधाओं के विस्तार और अधोसंरचना विकास के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। शहर के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।

200 निर्माण श्रमिकों एवं उनके बच्चों को मिलेगा 480 घंटे का तकनीकी प्रशिक्षण



श्रम मंत्री लखन लाल देवीगन एवं छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संश्लेषण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह की उपस्थिति में हुए इस अनुबंध के तहत प्रदेश के 200 पंजीकृत निर्माण श्रमिकों अथवा उनके बच्चों को कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 480 घंटे का आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार शुरू की जा रही इस पहल का उद्देश्य निर्माण श्रमिकों के परिवारों को आधुनिक तकनीकी कौशल से जोड़ना तथा उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को प्लास्टिक प्रोसेसिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग एवं एक्सट्रूजन जैसे तकनीकी क्षेत्रों में व्यावहारिक एवं रोजगारपरक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद प्रतिभागियों को संवेचित उद्योगों में रोजगार के अवसर प्राप्त करने में सहायता मिलेगी, जिससे उनके परिवारों की आय एवं आजीविका को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम ने किया सेवा संकल्प अभियान के मेगा हेल्थ कैंप का शुभारंभ



सशक्त एमसीबी सेवा संकल्प अभियान 2026 के अंतर्गत चिरमिरी के पोड़ी स्थित मंगल भवन में मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और चिरमिरी के महापौर रामनरेश राय की अध्यक्षता में हुए शिविर में 10 हजार लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार किया गया। शिविर में डॉ. अश्विनी राउत, कार्डिओलॉजिस्ट, हॉस्पिटल एसएमसी रायपुर, डॉ. उमेश चंद्रा, न्यूरोलॉजिस्ट, डॉ. हेमलता एवं डॉ. कल्पना, बालको हॉस्पिटल रायपुर, डॉ. मनोज गुप्ता, कार्डिओलॉजिस्ट, नारायणा हॉस्पिटल रायपुर, डॉ. जावेद परवेज, डॉ. करन सराफा, डॉ. भुवन शर्मा, यूरोलॉजिस्ट, डॉ. राकेश, पीडियाट्रिक्स, डॉ. अमित जैन, यूरोसर्जरी, डॉ. अभिषेक त्रिपाठी, आर्थोपेडिक तथा डॉ. संदीप अग्रवाल, यूरोलॉजिस्ट सहित विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं दीं। स्वास्थ्य मंत्री एवं जनप्रतिनिधियों ने शिविर में लगाए गए विभिन्न स्वास्थ्य स्टॉलों का निरीक्षण किया तथा उपलब्ध जांच, उपचार एवं अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली।

औद्योगिक विकास की मजबूत आधारशिला है एमएसएमई: विजय शर्मा



रायपुर में सीआईआई छत्तीसगढ़ राज्य परिषद द्वारा आयोजित दो दिवसीय एमएसएमई कॉन्फ्लेव 2.0 का डिप्टी सीएम विजय शर्मा और उद्योग

मंत्री लखन लाल देवांगन ने शुभारंभ किया। "नवाधार एवं सतत औद्योगिक विकास द्वारा एमएसएमई का सशक्तिकरण" विषय पर आयोजित कॉन्फ्लेव के पहले दिन 250 से अधिक उद्योगियों, नीति-निर्माताओं और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान ईज ऑफ़ इंडिंग बिजनेस, वित्तपोषण, तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और औद्योगिक विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस मौके पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ के औद्योगिक और आर्थिक विकास में छोटे उद्योगों, कारखानों और कार्यशालाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। एमएसएमई के विकास के लिए बेहतर कानून-व्यवस्था, सुगम सड़क संपर्क और त्वरित स्वीकृतियाँ आवश्यक हैं। राज्य सरकार इन तीनों क्षेत्रों में बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि इसके लिए शासन द्वारा उद्योग नीति बनाई गई है जिसमें एमएसएमई के साथ समावेशी विकास दिखाई देता है।

एशियन गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता टीम की संजू देवी को सीएम साय ने दी बधाई

एशियन गेम्स 2026 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला कबड्डी टीम की सदस्य और छत्तीसगढ़ की बेटी सुश्री संजू देवी ने



मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए संजू देवी को बधाई देते हुए उनका अभिनेदन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री

ने संजू देवी को 51 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सुश्री संजू देवी ने अपने उत्कृष्ट खेल, कठिन परिश्रम और हठ संकल्प से अंतरराष्ट्रीय मंच पर छत्तीसगढ़ और पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। उनकी यह उपलब्धि प्रदेश की बेटियों और युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं में अपार सामर्थ्य है। राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए बेहतर प्रशिक्षण, संसाधन और प्रोत्साहन मिले, ताकि वे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदेश और देश का नाम रोशन करें।

राज्य महिला आयोग ने सरगुजा संभाग के 25 प्रकरणों की सुनवाई की



छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू की अध्यक्षता में अंबिकापुर में सरगुजा संभाग स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई। संभाग स्तर पर यह पहली और प्रदेश स्तर पर आयोग की नौवीं जनसुनवाई थी। इसमें सरगुजा, सूरजपुर, जशपुर, कोरिया, बलरामपुर और मनेन्द्रगढ़-धिरमिरी-भरतपुर जिलों से संबन्धित 25 प्रकरणों पर सुनवाई हुई। इनमें से छह प्रकरण नसीबद्वी किए गए। जनसुनवाई में संभाग प्रभारी लक्ष्मी शुक्ला भी उपस्थित रहीं। आयोग ने पञ्चकारों को सुनने के बाद मानसिक प्रताड़ना से संबंधित एक प्रकरण में कलेक्टर को जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कार्यस्थल पर प्रताड़ना से जुड़े एक अन्य प्रकरण में सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को जांच के निर्देश दिए गए। डॉ. ममता साहू ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सौंपे गए प्रकरणों की जांच कर तत्वात्मक प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराएं, ताकि आगे की कार्यवाई की जा सके।

मुख्यमंत्री ने मदकूट्टीप के प्राचीन मंदिरों में की पूजा-अर्चना



मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मुंगेली जिले के पधरिया विकासखंड स्थित ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक स्थल हरिहर श्रेष्ठ केदार मदकूट्टीप पहुंचकर प्राचीन रामाशय एवं गणेश मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। मुख्यमंत्री ने भगवान से छत्तीसगढ़ की निरंतर प्रगति तथा प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में आयोजित कन्या पूजन में श्रद्धापूर्वक कन्याओं का पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया। इसके पश्चात वे कन्या भोज में शामिल हुए और प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्यमंत्री तोरुन साहू, डिप्टी सीएम अरुण साव, पूर्व राज्यपाल रमेश वैस, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन, विधायक धरमलाल कौशिक, विधायक अमर अग्रवाल, विधायक सुशांत शुक्ला एवं विधायक पुष्प लाल मोहले, कंठा के अध्यक्ष भूपेंद्र सवनी सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

संस्कृति मंत्री ने स्वच्छताकर्मियों का किया सम्मान

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सरगुजा जिले के नगर पंचायत लखनपुर में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे स्वच्छता कर्मचारियों



का सम्मान किया गया। स्वच्छताकर्मियों को उनके समर्पण और सेवानिवृत्ति के लिए उपहार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनके योगदान के प्रति आभार व्यक्त किया गया। संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि स्वच्छ और स्वस्थ समाज की नींव हमारे स्वच्छता कर्मियों के अथक परिश्रम पर टिकी है। उनका यह कार्य केवल

आजीविका का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के स्वास्थ्य और बेहतर जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण सेवा है। कार्यक्रम में स्वच्छता कर्मचारियों को उपहार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। सम्मान मिलने पर स्वच्छताकर्मियों में उत्साह दिखाई दिया। आयोजन के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि समाज को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन सेवा देने वाले स्वच्छता कर्मियों के श्रम, समर्पण और योगदान का सम्मान किया जाना चाहिए।

छत्तीसगढ़ में भूमि उपयोग नियमों में बड़ा बदलाव

छत्तीसगढ़ में विकास गतिविधियों को गति देने और भूमि उपयोग से जुड़ी प्रक्रियाओं को अधिक सरल, स्पष्ट एवं व्यावहारिक बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। आवास एवं पर्यावरण विभाग ने छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्तावित संशोधन में विभिन्न भूमि उपयोग श्रेणियों के लिए Negative List आधारित व्यवस्था अपनाने का प्रावधान किया गया है। यह पहल केंद्र सरकार के डीरिगुलेशन और अनुपालन बोर्ड कम करने के व्यापक सुधारों के अनुरूप है।



बस्तर: अब जब सांस ले रहा है, तो रास्ता कैसा हो ?

बस्तर को हमने बहुत लंबे समय तक एक ही नजर से देखा संघर्ष, नक्सल, बंदूक और असुरक्षा की नजर से।

इतनी लंबी अवधि तक यही तस्वीर हमारे सामने रखी गई कि बस्तर का दूसरा चेहरा, जो कहीं अधिक गहरा, पुराना और जीवंत है, लगभग ओझल हो गया। जबकि सच यह है कि बस्तर केवल संघर्ष का भूगोल नहीं है; वह सभ्यता, स्मृति, श्रम, जंगल, जल, कला और समुदाय का प्रदेश है। अब जब हालात पूरी तरह बदल गए हैं जब भय और असुरक्षा की रात व्यतीत हो गई, नया सबेरा आ गया तब सबसे बड़ा प्रश्न यही है—अब आगे क्या? और उससे भी बड़ा प्रश्न यह है—अब बस्तर का रास्ता कैसा हो? मेरे विचार से इसका उत्तर सीधा है—बस्तर को विकास चाहिए।

लेकिन ऐसा विकास नहीं जो बाहर से लाकर उस पर रख दिया जाए, बल्कि ऐसा जो यहीं की मिट्टी से निकले, यहीं के लोगों की आकांक्षाओं से बने और यहीं के समाज की भागीदारी से आकार ले। बस्तर को कागजों, फाहलों और योजनाओं से नहीं समझा जा सकता। उसे समझना हो तो उसके गांवों, उसके लोकविश्वास, उसकी निर्णय-प्रणाली और उसके सामाजिक बांधे को समझना होगा। उदाहरण के लिए बड़ेडोंगर को देखिए। वहां जब राजा नहीं रहा, तो लोगों ने नींदू को ही “लिमऊ राजा” का प्रतीक मान लिया। एक घंटान पर बैठकर, धूप-दीप के साथ, लोग सामूहिक रूप से निर्णय लेते हैं। यह परंपरा आज भी जीवित है। यह कोई साधारण लोककथा नहीं, बल्कि बस्तर की सामुदायिक बुद्धि का प्रमाण है। यह बताती

है कि यहां निर्णय ऊपर से थोपे नहीं जाते, बल्कि साथ बैठकर बनाए जाते हैं। यही वह दुनियादी बात है जिसे हमें बस्तर के विकास में भी समझना होगा। दिलचस्प बात यह है कि बस्तर शब्द में ही उसकी विकास-यात्रा के संकेत छिपे हुए हैं। एक मत यह है कि “बस्तर” शब्द “वस्त्र” से बना है। यदि ऐसा है, तो यह केवल भाषिक संयोग नहीं, बल्कि इस भूभाग की सांस्कृतिक और आर्थिक दिशा की ओर संकेत है। बस्तर का कोसा केवल एक कपड़ा नहीं, बल्कि उसकी पहचान, उसका शिल्प और उसकी बड़ी आर्थिक संभावना है। आज जब दुनिया प्राकृतिक, हस्तनिर्मित और टिकाऊ वस्तुओं की ओर लौट रही है, तब बस्तर का कोसा केवल परंपरा भर नहीं रह जाता; वह रोजगार, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण उद्योग और वैश्विक बाजार तक पहुंच का अवसर बन सकता है। यदि इसे सही डिजाइन, ब्रांडिंग, गुणवत्ता, विपणन और ई-कॉमर्स से जोड़ा जाए, तो कोसा बस्तर की अर्थव्यवस्था का बड़ा स्तंभ बन सकता है।

बस्तर शब्द की एक और लोक-व्याख्या “बांस तरी” से भी जुड़ी है—अर्थात् बांसों के नीचे या बांसों के बीच बसा भूभाग। यह व्याख्या भी केवल भाषा की जिज्ञासा नहीं, बल्कि बस्तर की भौगोलिक और आर्थिक सच्चाई की ओर संकेत करती है। बस्तर में बांस हर जगह है, लेकिन बांस आधारित उद्योग अभी भी अपनी पूरी संभावना तक नहीं पहुंचा। जबकि आज बांस केवल टोकरी या परंपरागत उपयोग की चीज नहीं रह गया है। उससे फर्नीचर, घरेलू उपयोग की वस्तुएं, सजावटी उत्पाद, अगरबत्ती स्टिक, पर्यावरण-अनुकूल पैकेजिंग, निर्माण सामग्री और कई प्रकार के सूक्ष्म उद्योग खड़े किए जा सकते हैं। बस्तर में बांस केवल वन-उत्पाद नहीं, बल्कि एक बड़ी हरित अर्थव्यवस्था की दुनियादा बन

सकता है। बस्तर की असली पूंजी जल, जमीन, जंगल और हाट-बाजार हैं। ये केवल संसाधन नहीं, बल्कि यहां के जीवन-तंत के चार स्तंभ हैं। हम अक्सर हाट-बाजार को सिर्फ एक बाजार मान लेते हैं, जबकि बस्तर में हाट का अर्थ कहीं अधिक व्यापक है। हाट यहां आर्थिक संस्था भी है, सामाजिक मंच भी और सांस्कृतिक स्पंदन भी। वहीं खरीद-विक्री होती है, वहीं खबरें चलती हैं, वहीं रिश्ते बनते हैं, वहीं समाज अपने को देखता है। कई जगहों पर आज भी भरोसा नकद से बढ़ा माध्यम है। इसलिए यदि बस्तर की स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, तो हाट-बाजार को मजबूत करना ही होगा—बेहतर व्यवस्था, भंडारण, स्थानीय उत्पादों के लिए जगह, महिला समूहों के लिए मंच और बाजार से सीधा जुड़ाव देकर।

जल की दृष्टि से भी बस्तर बेहद महत्वपूर्ण संभावना वाला क्षेत्र है। यह इलाका गोदावरी और महानदी के बीच फैला है। दक्षिण बस्तर में कई स्थानों पर भूमि की प्रकृति ऐसी है कि पानी बहुत गहराई तक समाने के बजाय बहकर निकल जाता है। इसका अर्थ है कि यहां जल-संचयन की संभावना अत्यंत बड़ी है। पुरानी कहावत “सात आगर सात कोरी” यूँ ही नहीं बनी। यह उस जल-संस्कृति की याद है जिसमें तालाब, आगर और सामुदायिक जल-संरचनाएं जीवन का हिस्सा थीं। बारसूर और बड़ेडोंगर आज भी इस परंपरा की गवाही देते हैं। यदि हम फिर से इस दिशा में गंभीरता से काम करें, तो तालाब, सिंचाई और मछली पालन तीनों मिलकर बस्तर की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा दे सकते हैं।

खेती की दृष्टि से भी बस्तर को नए नजरिए से देखने की जरूरत है। यहां समस्या खेती की कमी नहीं, बल्कि खेती की दिशा की है। कोदो, कुटकी, रागी और अन्य मोटे अनाज यहां की ताकत हैं।



तारुण प्रकाश सिन्हा

यही इस मिट्टी और जलवायु के सबसे स्वाभाविक साथी हैं। आज जब पूरा विश्व मिलेदस की ओर लौट रहा है, तब बस्तर के पास एक तैयार अवसर मौजूद है। लेकिन इसे केवल उत्पादन तक सीमित रखना पर्याप्त नहीं होगा। जब तक प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और बाजार तक पहुंच नहीं बनेगी, तब तक किसान को उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा।

जंगल तो बस्तर की पहचान है ही। महुआ, तेंदुपत्ता, घिरौंजी, साल बीज, इमली, लाख—ये सब केवल वन-उत्पाद नहीं, बल्कि हजारों परिवारों की आय का आधार हैं। लेकिन समस्या यह है कि कच्चा माल यहां से बाहर जाता है और असली मुनाफा कहीं और बनता है। यही वह जगह है जहां नीति को बदलने की जरूरत है। यदि वन-उत्पादों का प्रसंस्करण, पैकेजिंग और मूल्य संवर्धन बस्तर में ही हो, तो जंगल का लाभ सबसे पहले जंगल से जुड़े लोगों तक पहुंचेगा। बस्तर केवल संसाधनों का भूगोल नहीं, कौशल की सभ्यता भी है। यहां कोसा है, बाँस शिल्प है, धातु कला है, लकड़ी और घमड़े का पारंपरिक काम है। यहां हाथ केवल श्रम नहीं करते, वे सृजन भी करते हैं। जरूरत इस बात की है कि इन कौशलों को “ह्वर” कहकर छोड़ न दिया जाए, बल्कि इन्हें उद्योग, डिजाइन, प्रशिक्षण और बाजार से जोड़ा जाए। यही वह रास्ता है जहां बस्तर का भविष्य केवल कृषि या वन पर नहीं, बल्कि ग्रामीण रचनात्मक अर्थव्यवस्था पर भी टिक सकता है। फिर सवाल उठता है कि इतनी संभावनाएं होने के बावजूद हम अभी भी पूरी रफ्तार से आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? शायद इसलिए कि हमने कई बार संसाधनों को देखा, लेकिन लोगों की भागीदारी को पर्याप्त महत्व नहीं दिया। हमने योजनाएं बनाई, लेकिन हर बार यह सुनिश्चित नहीं किया कि लोग उनके निर्माता भी बनें। हमने बांधे खड़े किए, लेकिन हमेशा यह नहीं देखा कि उनमें स्थानीय समाज का स्वाभाविक कितना है। और बस्तर में यही अंतर सबसे निर्णायक है।

बस्तर में काम करना है, तो बस्तर के तरीके से करना होगा। यहां बैठना होगा, सुनना होगा, समझना होगा। यहां गांव को लाभार्थी नहीं, भागीदार मानना होगा। ग्राम सभा, पारंपरिक संस्थाएं, महिला समूह, युवा, वन समितियां और स्थानीय उत्पादक समूह—इन्हें विकास की प्रक्रिया का केंद्र बनाना होगा। बस्तर में प्रशासन की भूमिका सबसे प्रभावी तब होगी जब वह केवल लागू करने वाला तेल न रहकर विश्वास का सेतु बने। अब बस्तर के लिए यह पर्याप्त नहीं है कि हम सिर्फ यह कहें कि “स्थिति सुधर रही है।” असली सवाल यह है कि क्या बस्तर अब आर्थिक रूप से मजबूत, सामाजिक रूप से आत्मविश्वासी और सांस्कृतिक रूप से सम्मानित दिशा में बढ़ रहा है? स्थायी शांति केवल सुरक्षा से नहीं आती। वह तब आती है जब समाज को महसूस हो कि व्यवस्था में उसका हिस्सा है, निर्णय में उसकी आवाज है और विकास में उसका सम्मान है। इसलिए बस्तर को अब सिर्फ शांत नहीं, बल्कि समर्थ बनाना होगा।

बस्तर इस समय एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। वह अंधेरे से पूरी तरह बाहर नहीं आया है, लेकिन अब वह केवल अंधेरे की कहानी भी नहीं रह गया। यही वह समय है जब हमें बहुत सावधानी से तय करना होगा कि बस्तर के लिए अगला कदम क्या हो। हमें सिर्फ यह नहीं देखना है कि वहां क्या बनाना है, बल्कि यह भी तय करना है कि कैसे बनाना है, किसके साथ बनाना है और किसकी शर्तों पर बनाना है। अगर बस्तर की असली ताकत को एक वाक्य में कहा जाए, तो वह यह है कि यहां विकास की जमीन मौजूद है, बस उसे बस्तर की भाषा में पढ़ने की जरूरत है। और बस्तर की भाषा क्या है? जल की भाषा, जंगल की भाषा, हाट की भाषा, कोसा की भाषा, बाँस की भाषा और सबसे बढ़कर समुदाय की भाषा। “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” तभी सच होगा, जब उसमें ईमानदारी से एक ओर तत्व जुड़ जाए—“सबका प्रयास”। और बस्तर में “सबका प्रयास” तभी संभव है, जब विकास लोगों के बीच से निकले, लोगों पर से नहीं। यही बस्तर की असली दिशा है।

मुश्किल में आईपीएस डांगी

प्राथमिक जांच में सही पाए गए आईपीएस रतनलाल डांगी के खिलाफ यौन शोषण के आरोप, पुलिस ने हाईकोर्ट में बताया

छ सीसगढ़ के सस्पेंडेड आईपीएस अफसर रतन लाल डांगी के खिलाफ सब इंस्पेक्टर की पत्नी ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे। अब शुरूआती जांच में आरोप सही पाए गए हैं। पुलिस विभाग ने इसकी जानकारी हाईकोर्ट में दी है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं, जांच अधिकारी बदलने का प्रस्ताव भी भेजा गया है। डीजीपी की ओर से गृह सचिव को भेजे गए प्रस्ताव में आईपीएस दीपांशु काबरा को नया जांच अधिकारी और आईपीएस प्रशांत कुमार अग्रवाल को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी बनाने की जानकारी हाईकोर्ट में दी गई है। इस मामले में पीड़िता सब इंस्पेक्टर की पत्नी ने प्राथमिक जांच में पक्षपात का आरोप लगाते हुए रतन लाल डांगी को बचाने की कोशिश किए जाने का आरोप लगाया था।



पीड़िता ने किसी महिला आईपीएस अधिकारी से जांच कराने की मांग की थी। अब हाईकोर्ट की निगरानी में आगे की कार्रवाई होगी। दरअसल, पुलिस विभाग में पदस्थ सब इंस्पेक्टर की पत्नी ने आईपीएस डांगी पर यौन-उत्पीड़न का आरोप लगाया था। पीड़िता ने 15 अक्टूबर 2025 को पुलिस मुख्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि पिछले 7 साल से आईपीएस डांगी उसका शारीरिक और मानसिक शोषण कर रहे हैं। यौन-उत्पीड़न के आरोपों के बीच आईपीएस डांगी को पद से हटा दिया गया था। गृह विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता ने इसका आदेश जारी किया था। बाद में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि, इन आरोपों को रतनलाल डांगी ने झूठा बताया था। मामला अभी कोर्ट में चल रहा है।

ठीक से नहीं सुना गया मेरा पक्ष: पीड़िता

दरअसल, रतन लाल डांगी से जुड़े इस मामले में पीड़िता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में प्राथमिक जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया गया था कि, जांच के दौरान उसका पक्ष ठीक से नहीं सुना गया और आरोपी अधिकारी को बचाने की कोशिश की गई। पीड़िता ने निष्पक्ष जांच के लिए जांच अधिकारी बदलने की मांग की थी। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस विभाग से जांच की स्थिति और कार्रवाई को लेकर जानकारी मांगी गई। अब विभाग ने जांच अधिकारी बदलने का प्रस्ताव गृह सचिव को भेजने की जानकारी अदालत में दी है। याचिका में कहा गया था कि, शिकायत की जांच के लिए तत्कालीन आईजी आनंद छाबड़ा और तत्कालीन डीआईजी मिलना कुरें को जांच की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्हें इन दोनों अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं है। उनका कहना था कि एक अधिकारी आरोपी के बराबर रैंक के थे, जबकि दूसरी अधिकारी उनसे जूनियर थी। इसी वजह से उन्होंने दोनों को जांच से हटाकर किसी सीनियर आईएफएस या महिला आईएफएस अधिकारी से जांच कराने की मांग की थी।



पर्यटन की नई राह पर छत्तीसगढ़



हाईवे से घरोहर तक, विश्वस्तरीय सुविधाओं के साथ बढ़ रहा नया मॉडल

छत्तीसगढ़ की पहचान लेवे समय तक जंगल, झरने, जनजातीय संस्कृति और धार्मिक स्थलों तक सीमित करके देखी जाती रही है। लेकिन पर्यटन की बदलती दुनिया में अब किसी प्रदेश की खूबसूरती ही पर्याप्त नहीं होती। पर्यटक यह भी देखता है कि वहां पहुंचना कितना आसान है, रास्ते में सुविधाएं कैसी हैं, ठहरने की व्यवस्था कैसी है, स्थानीय भोजन और संस्कृति का अनुभव कितना सहज है और पूरे सफर में उसे कितना अच्छा अनुभव मिलता है।

छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल इसी बदलती ज़रूरत को ध्यान में रखकर पर्यटन को एक नए ढांचे में विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है। इस बदलाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रमुख राजमार्गों पर हाईवेक वे-साइड एमिनिटीज सेंटर विकसित करने की योजना है। रायपुर-जगदलपुर, रायपुर-बिलासपुर और बिलासपुर-कोरबा जैसे प्रमुख मार्गों पर प्रस्तावित ये केंद्र सड़क यात्रा को सुविधाजनक बनाने के साथ पर्यटन को भी नया आधार दे सकते हैं। योजना के तहत एक ही परिसर में ईवी चार्जिंग, पेडोल पंप, अलग-अलग वाहनों के लिफ्ट पार्किंग, स्वच्छ शौचालय, विश्राम कक्ष और फूड कोर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारी है।



हाईवे पर बनेगा पर्यटन का नया पड़ाव, सुविधा के साथ दिखेगा छत्तीसगढ़ का स्वाद

लेंबी दूरी की सड़क यात्रा में सबसे बड़ी परेशानी अक्सर रास्ते में सुप्लाइंग और साफ-सुथरी सुविधाओं की कमी होती है। प्रस्तावित वे-साइड एमिनिटीज सेंटर इसी अंतर को भरने की कोशिश है। पर्यटन मंडल के अनुसार इन केंद्रों को मल्टीप्लेक्स मॉडल की तरह विकसित करने की योजना है, जहां अलग-अलग जरूरतों के लिए रात्रिघो को एक ही स्थान पर सुविधाएं मिल सकें। कारों, टूरिस्ट बसों और भारी वाहनों के लिए अलग पार्किंग, 24 घंटे स्वच्छ शौचालय, विश्राम की सुविधा और ईवी चार्जिंग जैसे इंटीग्राम आने वाले समय में सड़क पर्यटन की तस्वीर बदल सकते हैं। खासकर इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते इस्तेमाल के बीच हाईवे पर चार्जिंग नेटवर्क पर्यटन यात्रा के लिए भी महत्वपूर्ण आधार बन रहा है। लेकिन इस योजना की सबसे दिलचस्प बात सुविधा और स्थानीय पहचान का मेल है। फूड कोर्ट में बड़े राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के साथ छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को भी स्थान देने की योजना है। चीला, फरा, ठेठरी, खुरमी, चीसेला, बरे-बासी, टैप्सरी और अंगकुर रोटी जैसे व्यंजन पर्यटकों को सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि प्रदेश की स्थानीय संस्कृति का स्वाद भी देंगे। ठीक वही बिंदु है जहां पर्यटन सुविधा आर्थिक गतिविधि में बदल सकती है। यदि बाहर से आने वाला पर्यटक रास्ते में रुकता है, स्थानीय भोजन करता है, स्थानीय उत्पाद खरीदता है और आसपास के पर्यटन स्थल तक जाता है तो उसका खर्च सीधे स्थानीय अर्थव्यवस्था से जुड़ता है।



धार्मिक पर्यटन का बढ़ता दायरा, अब नए केंद्र भी खींच रहे यात्रियों को

पर्यटन मंडल के आँकड़ों के अनुसार प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों में तेजी दिखाई दे रही है। 2024 में प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर करीब 3.15 करोड़ यात्राएं दर्ज हुई थीं, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर करीब 4.05 करोड़ पहुंच गई। रानी एक साल में लगभग 90 लाख यात्राओं की वृद्धि हुई। उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर यह करीब 28.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। इस वृद्धि में धार्मिक पर्यटन की भूमिका महत्वपूर्ण रही। राजिम और डोंगरगढ़ जैसे प्रमुख धार्मिक केंद्रों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। 2025 में दोनों स्थानों पर कुल मिलाकर करीब 1.96 करोड़ यात्राएं दर्ज हुईं, जो प्रदेश की कुल पर्यटन यात्राओं का लगभग 48.4 प्रतिशत है। राजिम में 2024 की करीब 78 लाख यात्राएं बढ़कर 2025 में 1.12 करोड़ हो गईं। डोंगरगढ़ में भी यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। इस तस्वीर का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू नए धार्मिक पर्यटन केंद्रों का उभरना है। कौशलमाता मंदिर चंद्रखुरी, शिवरीनारायण, गिरौदपुरी धाम, कुदरगढ़ और चंद्रहासिनी मंदिर चंदपुर को 2025 में पर्यटन केंद्रों की सूची में शामिल किया गया। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार इन पांच स्थानों पर पहले ही साल 95 लाख से अधिक यात्राएं दर्ज हुईं। इसका सीधा अर्थ यह है कि धार्मिक पर्यटन के लिए पर्यटकों का एक बड़ा आधार पहले से मौजूद है। जरूरत अब इस बात की है कि श्रद्धालु केवल दर्शन करके वापस न लौटें, बल्कि आसपास के दूसरे पर्यटन स्थलों तक भी पहुंचें, ठहरें और स्थानीय अर्थव्यवस्था से जुड़ें। इसी सोच से पर्यटन को एक दिवसीय यात्रा के बजाय बहुदिवसीय अनुभव में बदलने की कोशिश महत्वपूर्ण हो जाती है।

धार्मिक स्थलों से आगे, प्रकृति और संस्कृति को मिलेगा नया बाजार

एतौसगढ़ की सबसे बड़ी पर्यटन पूंजी उसकी विविधता है। बस्तर की जनजातीय संस्कृति, जलप्रपात और जंगल, सरगुजा की प्राकृतिक संपदा, सिरपुर की ऐतिहासिक विरासत, मोरमदेव की स्थापत्य कला, बारनवापारा का घन्टजीवन और अनेक धार्मिक केंद्र एक ही प्रदेश में अलग-अलग तरह के पर्यटन अनुभव उपलब्ध कराते हैं। पर्यटन मंडल की मौजूदा दिशा में अनुभव आधारित पर्यटन, होमस्टे, राम वन गमन परिषद, जनजातीय और ईको टूरिज्म तथा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। यही बदलाव एतौसगढ़ को पारंपरिक पर्यटन मंडल से आगे ले जा सकता है। पर्यटक केवल किसी जलप्रपात या मंदिर को देखने नहीं आता, वह स्थानीय जीवन को महसूस करना चाहता है। यह स्थानीय भोजन खाना चाहता है, गांव में रुकना चाहता है, हस्तशिल्प देखना चाहता है और प्रकृति के करीब समर बिताना चाहता है। होमस्टे और जनजातीय पर्यटन इसी जरूरत को पूरा करने का माध्यम बन सकते हैं। इसके साथ निजी निवेश की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। पर्यटन मंडल वैसाइड एमिनिटीज सेंटर के लिए पीपीपी मॉडल अपनाने की तैयारी कर रहा है। इस व्यवस्था में भूमि और गुणवत्ता से जुड़े मानक पर्यटन मंडल तय करेगा, जबकि निजी भागीदार निर्माण, संचालन और रखरखाव में निवेश करेंगे। पीपीपी मॉडल का महत्व केवल सरकारी खर्च कम करने तक सीमित नहीं है। इससे पर्यटन स्थलों पर पेशेवर संचालन, बेहतर सेवाएं और निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता लाने की संभावना बनती है। साथ ही स्थानीय रोजगार, परिवहन, होटल, भोजन, हस्तशिल्प और दूसरे छोटे कारोबारों के लिए भी अवसर पैदा हो सकते हैं।

अब लक्ष्य सिर्फ पर्यटक बढ़ाना नहीं, उनका अनुभव और स्वर्च भी बढ़ाना

पर्यटन की सफलता केवल इस बात से नहीं मापी जानी चाहिए कि कितने लोग किसी जगह पहुंचे। असली सवाल यह है कि पर्यटक यहां कितने समय रुका, उसने कितना खर्च किया और उस खर्च का कितना हिस्सा स्थानीय लोगों तक पहुंचा। इसी दिशा में पर्यटन मंडल अनुभव आधारित पर्यटन को बढ़ाने की बात कर रहा है। हालिया पहलों में पर्यटन स्थलों की वास्तविक स्थिति का जाकलन करने के लिए अधिकारियों के स्तर पर सड़क, शौचालय, नेटवर्क और दूसरी सुविधाओं की जमीनी समीक्षा पर भी जोर दिखाई दे रहा है। 2026 के बजट में भी धार्मिक पर्यटन और विरासतों को प्रदेश के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक केंद्रों से परिचित कराने के लिए मुख्यमंत्री आस्था पथ योजना तथा एतौसगढ़ युवा दर्शन योजना जैसे प्रावधान किए गए हैं। इस पूरी तस्वीर को साथ रखकर देखें तो एतौसगढ़ पर्यटन अब केवल पर्यटन स्थल विकसित करने की योजना नहीं रह गया है। सड़क, सुविधा, संस्कृति, स्थानीय भोजन, डिजिटल प्रचार, निजी निवेश, होमस्टे और नए पर्यटन सॉफ्ट को एक साथ जोड़ने की कोशिश दिखाई देती है। एतौसगढ़ के पास पर्यटन की प्राकृतिक और सांस्कृतिक संपदा पहले से मौजूद है। चुनौती उसे ऐसे अनुभव में बदलने की है, जिसके लिए पर्यटक प्रदेश में ज्यादा समय बिताना चाहे। लाईवे पर आधुनिक सुविधा केंद्र इस यात्रा का प्रदेश द्वार बन सकते हैं, जबकि बस्तर के जंगल, सरगुजा की प्रकृति, सिरपुर की विरासत, धार्मिक धाम और एतौसगढ़ी ध्यानपान उस अनुभव को पूरा कर सकते हैं। अगर इन प्रयासों में सुविधा, स्वच्छता, कनेक्टिविटी, स्थानीय भागीदारी और गुणवत्तापूर्ण संचालन लगातार मजबूत होता है, तो पर्यटन प्रदेश की अर्थव्यवस्था में केवल यात्रियों की संख्या बढ़ाने वाला क्षेत्र नहीं रहेगा, बल्कि रोजगार, स्थानीय उद्यम और सांस्कृतिक पहचान को आगे बढ़ाने वाला बड़ा माध्यम बन सकता है।

वोटर लिस्ट पर राजनीति

एसआईआर के बाद नामों को लेकर आमने-सामने भाजपा और कांग्रेस



ह तीसरा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद सियासी बहस का केंद्र अब यह है कि सूची से कितने नाम हटे, उनमें कितने लोग वास्तव में अपात थे और कितने पाल मतदाता किसी कारण से बाहर रह गए। कांग्रेस ने करीब 25 लाख नाम गायब होने का आरोप लगाकर प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। भाजपा ने इसे चुनावी हार से उपजा राजनीतिक आरोप बताया है। दोनों दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं, लेकिन इस बहस का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष उन नागरिकों का है, जो पाल होने के बावजूद मतदाता सूची में अपना नाम नहीं पा रहे हैं।

भारत निर्वाचन आयोग ने एसआईआर के बाद पाल मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इस पहल का उद्देश्य उन लोगों की पहचान करना है, जिनके नाम पुरानी सूची में दर्ज थे, लेकिन नई सूची में नहीं मिल रहे हैं। इसके साथ ही पहली बार मतदान करने जा रहे युवाओं को भी पंजीकरण का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मतदाता सूची की शुद्धता का अर्थ केवल अपात नामों को हटाना नहीं, बल्कि प्रत्येक पाल नागरिक का नाम सुनिश्चित करना भी है। पुनरीक्षण की प्रक्रिया तभी अपने उद्देश्य को पूरा करती है, जब उसमें गलत प्रविष्टियों को सुधारने के साथ छूटे हुए लोगों को जोड़ने की व्यवस्था भी प्रभावी हो।

25 लाख नामों का दावा और राजनीतिक आरोपों के बीच आंकड़ों की कसौटी

पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता मोहम्मद अकबर ने आरोप लगाया है कि एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची से करीब 24 लाख 99 हजार 823 नाम गायब हैं। उनके अनुसार, इनमें 19 लाख 13 हजार 540 मतदाताओं को स्थानांतरित या अनुपस्थित श्रेणी में रखा गया है। अकबर ने इन आंकड़ों की तुलना 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच रहे कुल मतों के अंतर से करते हुए कहा कि नामों की संख्या चुनावी अंतर से कई गुना अधिक है। कांग्रेस की आपत्ति का केंद्र यह है कि किसी मतदाता का

अस्थायी रूप से घर से बाहर होना उसके मतदान के अधिकार को समाप्त करने का आधार नहीं बनना चाहिए। रोजगार, पढ़ाई, मौसमी मजदूरी या पारिवारिक कारणों से लोग अपने सामान्य निवास से दूर रह सकते हैं। ऐसे मामलों में व्यक्तिगत सत्यापन और संबंधित नागरिक को अपना पक्ष रखने का अवसर दिए जाने की मांग कांग्रेस कर रही है। हालांकि, मतदाता सूची से नाम गायब होने के आंकड़े और उसके कारणों की पुष्टि अलग-अलग स्तर पर जरूरी है। किसी नाम का पुरानी सूची में होना और नई सूची में नहीं मिलना अपने आप यह साबित नहीं करता कि उसे गलत तरीके से हटाया गया। इसी तरह, अनुपस्थित या स्थानांतरित दर्ज किए गए प्रत्येक व्यक्ति को अपात मान लेना भी उचित नहीं होगा। वास्तविक स्थिति जानने के लिए

नामवार रिकॉर्ड, हटाने का आधार और संबंधित मतदाता की मौजूदा पालता की जांच आवश्यक है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विजय शंकर मिश्रा ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि बिपक्ष अपनी चुनावी हार से ध्यान हटाने के लिए निर्वाचन आयोग जैसी स्वतंत्र संवैधानिक संस्था पर सवाल उठा रहा है। भाजपा का पक्ष है कि मतदाता सूची की प्रक्रिया को राजनीतिक आरोपों के बजाय नियमों और तथ्यों के आधार पर देखा जाना चाहिए। इस तरह दोनों दलों के दावों के बीच वास्तविक सवाल यह है कि उपलब्ध आंकड़ों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच किस तरह हो। राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन मतदाता सूची से जुड़े प्रत्येक विवाद का समाधान दस्तावेजों, सत्यापन और निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर ही संभव है।



घर-घर सत्यापन से पहली बार वोट देने वाले युवाओं तक

निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, बृहत् लेवल अधिकारी राजी बीएलओ मौजूदा मतदाता सूची का प्री-एसआईआर सूची से मिलान करेंगे। इस प्रक्रिया में ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी, जिनके नाम पुरानी सूची में थे, लेकिन वर्तमान सूची में दर्ज नहीं हैं। इसके बाद संबंधित मतदाताओं के घर जाकर उनकी स्थिति का सत्यापन किया जाएगा। पात्र पाए जाने वाले नागरिकों के नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। आयोग ने बीएलओ को हर सप्ताह कम से कम 20 से 25 ऐसे मतदाताओं तक पहुंचने और करीब एक महीने में यह प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य दिया है। बृहत्तर तैयारी सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बृहत् लेवल एजेंटों के साथ साझा करने की व्यवस्था भी अभियान का हिस्सा है। आवेदन और सत्यापन रिपोर्टें संबंधित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी तक पहुंचेंगी, जहाँ नियमानुसार आगे की कार्यवाई होगी। इस अभियान का दूसरा अहम पक्ष 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं का पंजीकरण है। बड़ी संख्या में युवा शिक्षा, रोजगार या अन्य कारणों से अपने मतदाता पंजीकरण को लेकर जागरूक नहीं हो पाते। ऐसे पात्र युवाओं और पहली बार वोट देने

वालों से फॉर्म-8 भ्रमाने पर जोर दिया जाएगा। आयोग ने मतदाता पंजीकरण को सतत प्रक्रिया बताया है। राजी निर्धारित पात्रता पूरी करने वाला नागरिक सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है। विशेष अभियान के दौरान बृहत् स्तर पर शिक्षित लगाने और व्यवस्थित प्रचार की योजना भी है। रैन बसेरो, मजदूर बस्तियाँ, बेघर नागरिकों और वंचित समूहों तक पहुंचने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्वीप गतिविधियों के जरिए लोगों को नाम जोड़ने और पंजीकरण की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी अभियान को निर्धारित समीक्षा करेंगे। छत्तीसगढ़ में स्थानीय निकायों की निर्वाचक नामावली को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग अजय सिंह ने भी शुद्ध और त्रुटिरहित सूची को निष्पक्ष चुनाव का आधार बताया है। उन्होंने निर्वाचक नामावली प्रेक्षकों की बीफिंग में संभावित त्रुटियों को दूर करने और सभी योग्य मतदाताओं के नाम दर्ज करने पर जोर दिया। यह ध्यान रखना जरूरी है कि स्थानीय निकायों की निर्वाचक नामावली से संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया और विधानसभा-लोकसभा चुनावों के लिए भारत निर्वाचन आयोग की

मतदाता सूची अलग संस्थागत व्यवस्थाओं के अंतर्गत आती है। फिर भी दोनों का मूल उद्देश्य पात्र मतदाताओं की सही पहचान और पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया है। आश्विनकार, मतदाता सूची पर छिड़ी यह बहस किसी एक दल के आरोप या दूसरे दल के बचाव तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। यदि सूची में अपात्र नाम हैं, तो नियमों के अनुसार उनका सुधार जरूरी है। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम छूट गया है, तो उसे वापस जोड़ने का रास्ता भी सरल और समुचित होना चाहिए। राजनीतिक दलों को भी बृहत् स्तर पर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सत्यापन में सहयोग करना चाहिए, ताकि विवाद तथ्यों के आधार पर सुलझ सकें। मतदाता सूची लोकतंत्र का प्रवेश-द्वार है। इसकी विश्वसनीयता तभी कायम रह सकती है, जब नाम जोड़ने और हटाने, दोनों प्रक्रियाओं में समान सावधानी बरती जाए। एसआईआर के बाद शुरू होने वाला विशेष अभियान इस कमीटी पर महत्वपूर्ण होगा कि यह छूटे हुए पात्र नागरिकों तक कितनी प्रभावी ढंग से पहुंचता है। चुनाव की निष्पक्षता पर भरोसा केवल दावों से नहीं, बल्कि ऐसी प्रक्रिया से बनेगा जिसमें हर पात्र मतदाता को अपना नाम दर्ज कराने और अपनी बात रखने का अवसर मिले।



85 पदकों की चमक लेकिन सवाल भी बाकी

एशियन गेम्स में भारत ने रचा इतिहास
तो कई मोर्चों पर दिखी कमजोरी



आ इचौ-नागोया एशियन गेम्स में भारत का सफर 85 पदकों के साथ समाप्त हुआ। 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदकों के इस प्रदर्शन ने भारतीय खेलों की ताकत और कमजोरियों दोनों को सामने ला दिया। पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पर रहा। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया उससे आगे रहे, जबकि समान संख्या में स्वर्ण जीतने के बावजूद उज्बेकिस्तान कम रजत पदकों के कारण भारत से पीछे रहा। 85 पदकों का आंकड़ा अपने आप में शानदार है, लेकिन इसे 2023 के प्रदर्शन के साथ रखकर देखें तो तस्वीर थोड़ी अलग दिशाई देती है।

पिछले एशियन गेम्स में भारत ने 106 पदक जीते थे, जिनमें 28 स्वर्ण शामिल थे। यानी कुल पदकों और स्वर्ण पदकों दोनों में कमी आई। इसलिए इस अभियान को केवल पदकों की संख्या के आधार पर

सफल या असफल करार देना उचित नहीं होगा। असली कहानी उन खेलों में छिपी है जहां भारत ने इतिहास बनाया और उन खेलों में भी, जहां प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा। भारत की 85 पदकों की उपलब्धि के बावजूद एशियाई खेलों की सबसे बड़ी तस्वीर चीन के दबदबे से तय होती है।

चीन ने 169 स्वर्ण जीतकर बाकी देशों से बहुत बड़ी दूरी बनाए रखी। भारत के 21 स्वर्ण उसकी तुलना में काफी पीछे रहे। यह अंतर केवल जनसंख्या या संसाधनों का सवाल नहीं है। खेल संस्कृति, स्कूल स्तर की प्रतियोगिताएं, प्रशिक्षकों की गुणवत्ता, वैज्ञानिक प्रशिक्षण, खेल विज्ञान, प्रतिभा की पहचान और लंबे समय की तैयारी मिलकर किसी देश की खेल ताकत बनाते हैं। भारत को यदि एशिया में चीन की चुनौती के करीब पहुंचना है तो कुछ सफल खिलाड़ियों के भरोसे से आगे बढ़कर खेलों का व्यापक बांधा मजबूत करना होगा।

महिला खिलाड़ियों ने बदली तस्वीर

इस एशियन गेम्स की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में भारतीय महिला खिलाड़ियों का उभार रहा। लंबे अंतराल के बाद ऐसा हुआ जब महिलाओं के व्यक्तिगत और महिला वर्ग के मुकाबलों में भारत ने पुरुषों से अधिक स्वर्ण जीते। महिला स्पर्धाओं में भारत के खाले में 11 स्वर्ण आए, जबकि पुरुष वर्ग से 7 स्वर्ण मिले। मिश्रित स्पर्धाओं ने 3 स्वर्ण जोड़े। यह केवल आंकड़ा नहीं है। यह भारतीय खेल व्यवस्था में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और प्रतिस्पर्धी क्षमता का संकेत भी है। निशानेबाजी, तीरंदाजी, गोल्फ, मुक्केबाजी, एथलेटिक्स और हॉकी में महिला खिलाड़ियों ने अपनी मौजूदगी मजबूती से दर्ज कराई। प्रणवी ठाकुर का प्रदर्शन इसका बड़ा उदाहरण रहा। उन्होंने व्यक्तिगत गोल्फ में स्वर्ण जीतकर इतिहास रचा और इस खेल में भारत के लंबे शिवाजी इंतजार को समाप्त किया। तीरंदाजी में कुमकुम मोहोड और निशानेबाजी में नीरु छांडा ने भी अपने प्रदर्शन से भारतीय महिला खिलाड़ियों की नई पीढ़ी की ताकत दिखाई।



तीरंदाजी, मुक्केबाजी और कुश्ती में मजबूत पकड़

तीरंदाजी भारत के सबसे भरोसेमंद खेलों में बना रहा। भारतीय दल ने इस खेल में नौ पदक जीते, जिसमें पांच स्वर्ण शामिल रहे। कंपाउंड वर्ग में भारत ने तीनों टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण हासिल किए। रिकर्व वर्ग में भी भारतीय खिलाड़ियों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया और सभी पांच स्पर्धाओं में पदक हासिल किए। कुमकुम मोहोद का व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा। उनके प्रदर्शन ने न केवल पदक दिलाया, बल्कि लॉस एंजिल्स ओलंपिक के लिए कोटा भी सुनिश्चित किया। तीरंदाजी में लगातार मजबूत प्रदर्शन यह बताता है कि भारत ने इस खेल में प्रतिभा खोज, प्रशिक्षण और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का एक प्रभावी ढांचा तैयार किया है। जहाँ कुछ पारंपरिक खेलों में गिरावट आई, वहीं मुक्केबाजी और कुश्ती ने भारत को राहत दी। मुक्केबाजी में तीन स्वर्ण मिले, जो एशियाई खेलों में इस खेल का भारत का सबसे सफल स्वर्ण अभियान रहा। लवलीना बोरगोहेन का स्वर्ण विशेष रहा। वह मेरी कॉम के बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज बनीं। कुश्ती में भारत ने छह पदक जीते। अमन सहरावत और सुजीत कलकल के स्वर्ण ने इस खेल में भारत की वापसी का संकेत दिया। लंबे समय के बाद कुश्ती में ऐसा प्रदर्शन देखने को मिला जिसने पुराने गौरव की राह दिखाई। मीराबाई चानू का रजत भी महत्वपूर्ण रहा। यह एशियाई खेलों में उनका पहला पदक था और लंबे अंतराल के बाद भारतीयों ने भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बनी।

निशानेबाजी में पदक आए, लेकिन पुरानी ऊंचाई गायब रही

निशानेबाजी ने कई ऐतिहासिक क्षण जरूर दिए, लेकिन कुल मिलाकर यह क्षेत्र पिछली बार जैसी सफलता नहीं दोहरा सका। भारत को इस बार निशानेबाजी में तीन स्वर्ण मिले, जबकि पिछले अभियान में सात स्वर्ण आए थे। सुरुचि सिंह और कमलजीत ने मिश्रित एयर पिस्टल में एशियाई रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण जीतकर इतिहास बनाया। नीरू ण्डा ने महिला ट्रैप में स्वर्ण हासिल कर नया इतिहास रचा और मिश्रित ट्रैप में भी स्वर्ण अपने नाम किया। फिर भी सवाल बना रहेगा कि भारत इस खेल में पिछली सफलता को कायम क्यों नहीं रख सका। एशियाई स्तर पर चीन जैसी ताकतों के सामने भारत को निशानेबाजी में पदकों की निरंतरता बनाए रखने के लिए ज़मीनी स्तर से लेकर उच्च प्रदर्शन केंद्रों तक रणनीति पर फिर विचार करना होगा। भारत को सबसे ज्यादा 24 पदक एथलेटिक्स से मिले, लेकिन स्वर्ण सिर्फ एक रहा। यह आंकड़ा अपने भीतर विरोधाभास लिए हुए है। बड़ी संख्या में पदक बताती है कि भारतीय एथलीट कई स्पर्धाओं में पदक की दौड़ तक पहुंच रहे हैं, लेकिन स्वर्ण में बदलने की क्षमता अभी उतनी मजबूत नहीं हुई है। श्वेता रामराज इस अभियान की प्रमुख खिलाड़ियों में रहीं। उन्होंने 400 मीटर बाधा दौड़ में पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा और रिले स्पर्धाओं में भी पदक जीते। गुलवीर सिंह ने लंबी दूरी की अलग-अलग स्पर्धाओं में तीन पदक जीतकर शानदार निरंतरता दिखाई। सावन बरवाल ने माराथन में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ रजत जीता। लेकिन पिछले अभियान में एथलेटिक्स से छह स्वर्ण आए थे और इस बार केवल एक। यह गिरावट भारतीय एथलेटिक्स के लिए सबसे बड़ी चिंता है।



टीम खेलों में भारत की वादशाहत

अगर इस अभियान की सबसे चमकदार तस्वीर तलशनी हो तो वह टीम खेलों में दिखाई देती है। क्रिकेट, कबड्डी और हॉकी में पुरुष और महिला दोनों वर्गों ने स्वर्ण जीतकर भारतीय दबदबा कायम रखा। हॉकी में महिला टीम ने लंबे अंतराल के बाद एशियाई विजितां अपने नाम किया, जबकि पुरुष टीम ने अपना विजितां बरकरार रखा। इससे भी बड़ी उपलब्धि यह रही कि दोनों टीमों ने लॉस एंजिल्स ओलंपिक के लिए सीधे प्रवेश हासिल कर लिया। कबड्डी में भी भारत ने दोनों विजितां अपने पास रखे। क्रिकेट में पुरुष और महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण जीतकर इस खेल में भारत की गहराई दिखाई। यह प्रदर्शन बताता है कि जब भारतीय टीम खेल में प्रतिभा, संसाधन और सामूहिक रणनीति एक साथ काम करते हैं तो भारत एशिया में शीर्ष स्तर पर पहुंच सकता है।

कई खेलों में पहली बार इतिहास

भारत की उपलब्धियां केवल स्वर्ण पदकों तक सीमित नहीं रहीं। मिश्रित मार्शल आर्ट्स में सुधिका तिरियाल ने भारत को पहला पदक दिलाया। रोडिंग में पुरुष डबल स्कल्स का कांस्य भी ऐतिहासिक रहा। सेपकटकरा में भारत ने पहली बार पदक जीता। स्वर्धेश में अनाहत सिंह ने महिला एकल में रजत जीतकर नया अद्यतन लिखा। टेबल टेनिस में भी भारत ने मिश्रित युगल का कांस्य हासिल किया। इन परिणामों का महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि एशियन गेम्स केवल पदक जीतने का मेघ नहीं, बल्कि उन खेलों में भविष्य की दिशा तय करने का अवसर भी है जिनमें भारत अभी शुरुआती दौर में है।

2028 की तैयारी का संदेश

आइवी-नागोरा से भारत को सबसे बड़ा संदेश यही मिला है कि देश के पास प्रतिभा की कमी नहीं है। कई नए खिलाड़ी सामने आए, महिलाओं ने मजबूत प्रदर्शन किया, टीम खेलों में दबदबा कायम रहा और कई खेलों में पहली बार पदक मिले। लेकिन 106 से छटकर 85 पदक और 28 से छटकर 21 स्वर्ण यह भी बताते हैं कि केवल कुछ क्षेत्रों में मजबूत होना पर्याप्त नहीं है। निशानेबाजी और एथलेटिक्स जैसे बड़े पदक देने वाले खेलों में गिरावट की भरपाई लंबे समय तक नहीं की जा सकती। लॉस एंजिल्स ओलंपिक तक अब भारत के पास अपनी कमजोरियों को पहचानकर सुधारने का अवसर है। हॉकी की दोनों टीमों ने टिकट हासिल कर लिया है, तीरंदाजी में ओलंपिक कोटा मिला है और कई युवा खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्षमता साबित की है। इसलिए आइवी-नागोरा को भारत की मंजिल नहीं, बल्कि अगले बड़े अभियान की तैयारी मानना ज्यादा उचित होगा। 85 पदकों की चमक उल्लास देती है, लेकिन 2028 की चुनौती इससे कहीं बड़ी है। भारत को अब इतिहास बनाने वाले प्रदर्शन को अपवाद नहीं, बल्कि निरामित उपलब्धि में बदलना होगा।

छत्तीसगढ़ के शक्तिपीठ

प्रदेश के हर कोने में अनेक रूपों में विराजमान हैं देवियां

छत्तीसगढ़ में अनादि काल से शिवोपासना के साथ साथ देवी उपासना भी प्रचलित है। छत्तीसगढ़ में कई प्रमुख शक्तिपीठ हैं जो पूरे देश, प्रदेश में चर्चित हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख शक्तिपीठों में रतनपुर, चंदपुर, डोंगरगढ़, मल्हार और दंतेवाड़ा प्रमुख हैं। रतनपुर में महामाया, चंदपुर में चंदसेनी, डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी और दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी देवी विराजमान हैं। लेकिन अम्बिकापुर में महामाया और समलेश्वरी देवी विराजित हैं और ऐसा माना जाता है कि पूरे छत्तीसगढ़ में महामाया और समलेश्वरी देवी का विस्तार अम्बिकापुर से ही हुआ है। शायद हमें में आदि तत्व को मातृरूप मानने की सामाजिक मान्यता है; उसके अनुसार नारी पूजनीय माने जाने लगी। शक्ति स्वरूपा मां भवानी छत्तीसगढ़ की अधिष्ठात्री हैं। वहां के सामंतों, राजा-महाराजाओं, जमींदारों आदि की कुलदेवी के रूप में प्रतिष्ठित आज श्रद्धा के केंद्र बिंदु हैं। छत्तीसगढ़ में देवियां अनेक रूपों में विराजमान हैं, श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ इन स्थलों को शक्तिपीठ की मान्यता देने लगी है। प्राचीन काल में देवी के मंदिरों में ज्वारा बोई जाती थी और अखंड ज्योति कलश प्रज्वलित की जाती थी जो आज भी अनवरत जारी है। श्रद्धा के प्रतीक कई स्थलों में सुख, शांति और समृद्धि के लिये बलि दिये जाने की परंपरा है।



मां अंगारमोती मंदिर, गंगरेल, धमतरी

धमतरी के गंगरेल स्थित मां अंगारमोती मंदिर शक्ति का वो पीठ है, जहां हर किसी की मनोकामना पूरी होती है। वहां हर साल धमतरी और आसपास के 52 गांव के देवी-देवता दीवाली के बाद मंडई में शामिल होते हैं। अंगारमोती मां के आशीर्वाद से निरंतरता महिलाओं को संतान सुख मिलता है। साल 1973 में गंगरेल बांध बनने के पहले इस क्षेत्र में 52 गांव का वजूद था। गंगरेल बांध के डूब में आए 52 गांवों की अधिष्ठात्री देवी मां अंगारमोती की महिमा अपरंपर है। वहां के लोग बताते हैं कि धमतरी में गंगरेल बांध के बनने से पहले वहां कुल 52 गांव हुआ करते थे। इन गांवों की स्थापना से पहले ही वहां माता की मूर्ति स्वतः जमीन से प्रकट हुई। इस तरह इन गांवों के लोग अंगारमोती माता को अपनी अधिष्ठाता देवी मानने लगे। बांध बनते-वक़्त माता की मूर्ति को मूल स्थान से हटाकर दूसरे मंदिर में स्थापित

किया गया। माता अंगारमोती की मूर्ति को उस जगह से 40 साल पहले बैलगाड़ी के जरिए ग्राम विड़कडीटोला लाया गया। बाद में इसे गंगरेल बांध के अंतिम छोर में पुनर्स्थापित किया गया। 1999 से मां अंगारमोती मंदिर के संरक्षण और देखरेख की जिम्मेदारी के लिए ट्रस्ट बनाया गया। अब इसका संचालन गौड़ समाज की ओर से किया जाता है। मां अंगारमोती की श्रद्धा छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि कई राज्यों तक फैली है। सुरक्षा की दृष्टिकोण से मंडई क्षेत्र में पुलिस की इस्ट्री के साथ-साथ पुलिस यातायात की टीम तैनात की जाती है। आज भी निरंतर उनके दर पर आस्था की ज्योति जलती है। पूर्व में इन गांवों की टापू पर स्थित मां अंगारमोती की मूर्ति को बांध बनने के बाद बांध किनारे ही स्थापित कर दिया गया। अभी भी 52 गांव के ग्रामीण शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए मां अंगारमोती के दरबार पहुंचते हैं।

मां महामाया देवी, रतनपुर

रतनपुर में स्थित मां महामाया मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। देवी महामाया को कोसलेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है, जो पुराने दक्षिण कोसल क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। परंपरागत रूप से महामाया रतनपुर राज्य की कुलदेवी हैं। माना जाता है कि सती की मृत्यु से व्यथित भगवान शिव उनके मृत शरीर को लेकर तोंडव करते हुए झरोड़े में भटकते रहे। इस समय माता के अंग जहां-जहां गिरे, वहीं शक्तिपीठ बन गए। इन्हीं स्थानों को शक्तिपीठ रूप में मान्यता मिली। महामाया मंदिर में माता का चहिला स्कंध गिरा था। भगवान शिव ने स्वयं आधिभूत होकर उसे कोमारी शक्ति पीठ का नाम दिया था। इसीलिए इस स्थल को माता के 51 शक्तिपीठों में शामिल किया गया। भगवान शिव ने स्वयं आधिभूत होकर इसे कोमारी शक्तिपीठ का नाम दिया था। माना जाता है कि नवरात्र में वहां की गंधु पूजा कभी निष्फल नहीं होती। दुर्गा सप्तशती के साथ ही

देवी पुराण में महामाया के बारे में जो कुछ लिखा है, ठीक उन्हीं रूपों के दर्शन रतनपुर में विराजी महामाया के रूप में होती हैं। महामाया मंदिर में शक्ति के तीनों रूप दिखाई देते हैं। तीनों रूपों में समाहित मां के स्वरूप को महामाया देवी की संज्ञा दी गई है। वहां प्रातःकाल से देर रात तक भक्तों की भीड़ लगी रहती है। मंदिर के संरक्षक कालभैरव को माना जाता है, जिनका मंदिर रतनपुर शहर पहुंचने से पहले ही मंदिर के ही रास्ते पर स्थित है। वह एक लोकप्रिय धारणा है कि महामाया मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों को भी अपनी तीर्थयात्रा पूरी करने के लिए कालभैरव के मंदिर जाने की आवश्यकता होती है। चैत्र और क्वार नवरात्र के दौरान देवी मां की प्रसन्न करने के लिए ज्योतिर्कलश जलाया जाता है। नवरात्र में मां महामाया के दर्शन करने के लिए लाखों भक्त वहां आते हैं और उनकी मांगी हर मनोकामना मां पूरी होती है।



मां, दंतेश्वरी मंदिर, दंतवाड़ा, बस्तर

छत्तीसगढ़ के दंतवाड़ा का दंतेश्वरी मंदिर देश के 52 शक्तिपीठों में से एक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब विष्णु भगवान ने अपने चक्र से सती के शरीर को 52 भागों में विभक्त किया था, तो उनके शरीर के 51 अंग देशभर के विभिन्न हिस्सों में गिरे। 52 वें अंग उनका दांत गिरा था। इसलिए देवी का नाम दंतेश्वरी और जिस ग्राम में दांत गिरा था उसका नाम दंतवाड़ा पड़ा। बदलते वक़्त के साथ मंदिर की तस्वीर भी बदलती गई। लेकिन मां दंतेश्वरी का अपने भक्तों पर आशीर्वाद ऐसा रहा कि लोगों की आस्था और विश्वास समय के साथ बढ़ता गया। नवरात्र पर दंतवाड़ा में चारों ओर मां दंतेश्वरी के भक्तों का रैला लगता है। कोई जमीन पर लोटते हुए नारियल लेकर पहुंचता है, तो कोई मन्नत की चुनरी लेकर, कोई आशीर्वाद से अभिभूत होकर आता है। आदिकाल से मां दंतेश्वरी को बस्तर के लोग अपनी कुल देवी के रूप में पूजते हैं। ऐसा माना जाता है कि, बस्तर में होने वाला कोई

भी विधान माता की अनुमति के बिना नहीं किया जाता है। इसके अलावा तैलंगाना के कुछ जिले और महाराष्ट्र के गडचिरोली जिले के लोग भी मां दंतेश्वरी को अपनी इष्ट देवी मानते हैं। वहां के लोग भी बताते हैं कि काकतीय राजवंश जब वहां आ रहे थे तब हम कुछ लोग वहां रह गए थे। वैसे तो मां दंतेश्वरी बस्तर की इष्ट देवी हैं। लेकिन अब हर जाति, सम्प्रदाय के लोग माता को मानने लगे हैं। हम भी मां दंतेश्वरी को अपनी इष्ट देवी के रूप में पूजते हैं। डाकिनजी और शाकिनजी नदी के संगम पर स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर में स्थापित देवी दंतेश्वरी बस्तर क्षेत्र के चालुक्व राजाओं की कुल देवी थीं। इन्होंने ही इस मंदिर की स्थापना की थी। जिसका गर्भगृह करीब आठ सौ साल से भी पुराना है। चार भागों में विभाजित इस मंदिर का निर्माण दक्खिं छेली में हुआ था। इस मंदिर के अवयवों में गर्भगृह, महा मंडप, मुख्य मंडप और सभा मंडप शामिल हैं। गर्भगृह और महामंडप का निर्माण पत्थरी से किया गया है।



मां मरही माता मंदिर, भनवारटंक, मरवाही



गैरला-पेंड्रा-मरवाही जिले में जंगली व पहाड़ी के बीच अमरकंटक हिल रेंज में भनवारटंक नामक गांव में निवास करती हैं एक दिव्य शक्ति, जिन्हें सब मां मरही माता के नाम से जानते हैं। मरही माता के चमत्कारों की कहानी बिलासपुर कला पुर उत्तरीसगढ़ में प्रसिद्ध है और उत्तरीसगढ़ के हर कोने से मां के दर्शन के लिए श्रद्धालु आते हैं। कहते हैं मां के पावन मंदिर में जब चलते हुए जब कोई मां के दर्शन के लिए आता है मां उनके सारे दुखों को हर लेती है। तब जब वहां से गुजरती है, तो मां इनको रक्षा करती है। और भी कई रोचक बातें इस अद्भुत और दिव्य मंदिर से जुड़ी हैं। भनवारटंक का ये मंदिर प्रकृति कि गोद में बसा हुआ एक हिल स्टेशन के समान प्रतीत होता है। बिलासपुर-कटनी रेल रूट पर थोपसरा और थोडरी रेलवे स्टेशन के बीच स्थित एक छोटे से स्टेशन भनवारटंक में रेलवे ट्रैक के किनारे मरही माता का मंदिर है। मरही माता मंदिर वही इलाके में बहुत सी मान्यताएं हैं। यहां से

गुजरते वक्ता लोको पावरल्ट भी ट्रेन की रफ्तार कम कर देती है। मान्यता है कि मरही माता के आशीर्वाद से बिलासपुर-कटनी रेल रूट के जंगली और पहाड़ी क्षेत्र भनवारटंक में लोगों की हादसों से रक्षा होती है। यहां माता को प्रणाम करने के बाद ही लोग आगे की राफ़ा पूरी करते हैं। हर साल वर्षार और चैत्र नवरात्र पर यहां दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। भनवारटंक से लगे मां मरही माता मंदिर बिलासपुर-कटनी रेललाइन के किनारे है। यहां रोज-सकड़ो श्रद्धालु पटरियों पर चलते हुए पहुंचते हैं क्योंकि वहां सड़क नहीं है। मंदिर से कुछ ही दूरी पर भनवारटंक रेलवे स्टेशन है। श्रद्धालु पटरियों पर रहते हैं, इसलिए उनकी सुआ के लिए मंदिर समिति ने दो गड्डे लगा रखे हैं। किसी भी लाइन पर जैसे ही ट्रेन आती है, ये श्रद्धालुओं को सावधान करते हुए रेलवे ट्रैक पार नहीं करने देते। ट्रेन के जाते ही श्रद्धालु फिर पटरियों पर नज़र आने लगते हैं।

डिडिनेश्वरी देवी, मल्हार, बिलासपुर

बिलासपुर जिले का छोटा सा कस्बा है मल्हार। जहां अरपा, लीलागार और शिवनाथ नदी के बीच बसे मल्हार में मां डिडिनेश्वरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। डिडिनेश्वरी देवी की मूर्ति कलचुरि संवत् 900 की है। शुद्ध काले येनाइड से बनी मां डिडिनेश्वरी की प्रतिमा लोगों की आस्था का केंद्र है। डिडिनेश्वरी शब्द का अर्थ छत्तीसगढ़ में कुमारी देवी होता है। कुंवारी रूप शैलसुता शिव की पति के रूप में पाने के लिए तपस्या रत हुई। पश्चासन में विराजित तपोमुदा वाली देवी की भव्य गंभीर मुखाकृति है, जिनके नेत्र मूंदे हुए, सीम्य में मुदा भाव में लीन, सिंह छाल में विराजित हैं। मां डिडिनेश्वरी देवी सर्वथा, करपा, सुश्रुता सिद्ध देवी हैं। ऐसी मान्यता है कि इस मूर्ति से एक श्वास तरल की एबनि निकलती है, जिसे लोग माता रानी का चमत्कार बताते। यही वजह है कि

लोगों की इस मंदिर को लेकर खास श्रद्धा है, जो भी भक्त सच्चे मन से मन्नत लेकर वहां आता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। माता अपने दरबार से किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देती। यहां स्थानीय लोगों के अलावा पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश और देशभर से लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं। चैत्र और शारदीय नवरात्रि के दिनों में लोग माता डिडिनेश्वरी के रंग में रंग जाते हैं। गांव में भक्ति का माहौल रहता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मंदिर में भी विशेष पूजा-अर्चना व धार्मिक आराधन होते हैं। 1985 से हर वर्ष यहां पर मल्हार मखोत्सव का आराधन भी किया जा रहा है। मंदिर की देखरेख के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लोक न्यास ट्रस्ट मां डिडिनेश्वरी मंदिर स्थापित कर दिया है।



बागेश्वरी देवी, कुदरगढ़, सूरजपुर

उत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर है कुदरगढ़। यहां से करीब 800 मीटरों वाली विराचल पर्वत श्रेणी से जुड़ी हुई पहाड़ के ऊपर स्थित है देवी बागेश्वरी का दरबार। मां पार्वती का तपस्थली मां भगवती आदि शक्ति जगत जननी बागेश्वरी देवी कुदरगढ़ों का पावन धाम लाखों, करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। यहां हर साल चैत्र और ववस में नवरात्रि पर मेला लगता है। उत्तीसगढ़ की पंच शक्तिपीठों में कुदरगढ़ी में मां भगवती की ये शक्तिपीठ सबसे प्रमुख है। मां बागेश्वरी के दर्शन करने के लिए करीब एक हजार से ज्यादा सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है, तब मां के दर्शन होते हैं। मां बागेश्वरी के दर्शन करने और मन्नत मांगने उत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत

अन्य राज्यों के श्रद्धालु कुदरगढ़ पहुंचते हैं। सीढ़ियों को लोंघते हुए 1500 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर भक्त यद्युक्त के नीचे विराजमान मां बागेश्वरी के सामने शीश झुकाते हैं। चारों तरफ से हरे-भरे वनों और पहाड़ियों से घिरे मां बागेश्वरी धाम में पहुंचने के बाद हर भक्त एक अलग ही ताजगी महसूस करता है। हर तरफ बंदरों की टोलियां नजर आती हैं, जिन्हें देखने के बाद मन उत्साहित हो जाता है। 1500 फीट ऊंची पहाड़ी पर चढ़ने और उतरने के दौरान सीढ़ियों के रास्ते में प्रकृति की शुद्ध हवा चलती रहती है। इससे श्रद्धालुओं को अपनी थकान का पता ही नहीं चलता है। कुदरगढ़ देवी की मूर्ति लाल पथर की अष्टभुजी महिषासुर मर्दिनी स्वरूप की है। इस मंदिर के पास स्थित पेड़ पर नारियल बांधने से मांगी गई हर मुन्नद पूरी होती है।



मां कंकाली मंदिर, रायपुर

उत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के ब्राह्मणपारा में प्रतिस्थापित 700 साल से ज्यादा पुरानी है मां कंकाली का मंदिर। श्मशान घाट पर बने इस मंदिर में अस्त्र और शस्त्र के दर्शन भी होते हैं, लेकिन साल में सिर्फ एक बार दशहरा को। कहा जाता है कि दशहरे के दिन मां जगदंबा पूर्ण तेज में आती हैं। विजरादशमी पर माता का दूध, दही से अभिषेक किया जाता है। पूर्ण रूप से विशेष पूजा की जाती है और बलि देने की परंपरा रहती है। माता की कृपा से संतान प्राप्ति होती है। जो संतान की इच्छा लेकर आते हैं, माता उनको संतान प्रदान करती हैं। शहर की पुरानी बस्ती क्षेत्र में स्थित मां कंकाली मंदिर का इतिहास सबसे अलग और पुराना है। कंकाली मंदिर

का शस्त्रागार साल में केवल एक ही दिन दशहरा की सुबह खुलता है। फिर शाम ढलते ही शस्त्रागार पूरे एक साल के लिए बंद हो जाता है। इस दौरान दर्शनार्थियों की भारी भीड़ लगती है। लोग माता के सामने मत्था टेकते हैं और पुराने अस्त्र-शस्त्र के दर्शन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान राम और रावण का युद्ध हो रहा था तब देवी युद्ध के मैदान में प्रकट हुई थीं और श्रीराम को अस्त्रों व शस्त्रों से सुसज्जित किया था। बस इसी मान्यता के चलते इनके शस्त्रागार का महत्व बढ़ जाता है और लोग इसके दर्शन मात्र के लिए दूर-दूर से आते हैं। ये शस्त्रागार केवल दशहरा के दिन खुलता है क्योंकि इसी दिन राम ने रावण का वध किया था।

मां महिषासुर मर्दिनी, चैतुरगढ़, कोरबा

कोरबा जिले में उत्तीसगढ़ के कश्मीर चैतुरगढ़ में मां महिषासुर मर्दिनी का प्राचीन मंदिर है। चैतुरगढ़ की पहाड़ी पर स्थित मां महिषासुर मर्दिनी की 12 हाथों की मूर्ति, गर्भगृह में स्थापित है। मंदिर से 3 किलोमीटर दूर शंकर की गुफा स्थित है। यह गुफा एक सुरंग की तरह है। बताया जाता है कि यह गुफा 25 फीट लंबी है। लेकिन कोई गुफा के अंदर जा नहीं सकता। कुछ दूरी के बाद गुफा का मार्ग बेहद संकरा है। इसे शंकर खोल भी कहा जाता है। चैत्र और कुंवार के नवरात्रि में इन मंदिर में बेहद ही भव्य मेले का आयोजन होता है। मेले को देखने हजारों की संख्या में लोग भी आते हैं। इस मंदिर के आस-पास हनुमान, कालभैरव और शनिदेव आदि की मूर्तियां भी रखी हुई हैं। ऐसा कहा जाता है कि 8वीं सदी में मंदिर का निर्माण कलचुरी वंश के राजाओं ने करवाया था। चैतुरगढ़ किला उत्तीसगढ़ के 36 किलों में से एक है। यह किला भारत के सबसे मजबूत प्राकृतिक किलों में से एक है। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है। उत्तीसगढ़ का चैतुरगढ़ किला अपनी वास्तुकला, इतिहास और खूबसूरती के लिए पर्यटकों के बीच विख्यात है। चैतुरगढ़ किले को 'लाफागढ़ किले' के नाम से भी जाना

जाता है। यह किला उत्तीसगढ़ के 36 किलों में से एक है। चैतुरगढ़ किला 5 किलोमीटर की क्षेत्रफल में फैला हुआ है। आपको बता दें, चैतुरगढ़ किला भारत के सबसे मजबूत प्राकृतिक किलों में से एक है। साथ ही, यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है। चैतुरगढ़ किला 3,060 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ पर बसा हुआ है। कोरबा जिले से यह 70 किलोमीटर दूर चाली जिले (राजस्थान) से 19 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं इस किले में महिषासुर मर्दिनी मंदिर है। इसके साथ ही यह जगह अलग-अलग प्रकार की जड़ी-बूटियों, औषधियों और वन्य जीव-जंतुओं से भरी हुई है। किले का सफर यों तो रोमांचमयी होता है पर बरसात के समय किले का सफर करने में अलग ही मजा और सनसनाहट महसूस होती है। चैतुरगढ़ किले की दीवारें एक जैसी न होने की वजह से कई जगह छोटी तो कई जगह मोटी दिखाई देती हैं। किले के प्रवेश द्वार को वास्तुकला की दृष्टि से बड़ी ही बखूबी और तरीके से बनाया गया है। इसमें कई सारे स्तंभ और मूर्तियां भी देखने को मिलती हैं। साथ ही यहां पर एक बहुत बड़ी गुंबद है जो मजबूत स्तंभों पर बनायी गयी है। इस गुंबद को पांच खंभों के सहारे बनाया गया है।



चंद्रहासिनी देवी मंदिर, चंद्रपुर, सक्ती

महानदी के किनारे चंद्रहासिनी देवी का मंदिर स्थित है। नवरात्रि की पूर्व संक्रांति पर यहां प्रतिवर्ष एक भव्य उत्सव का आयोजन किया जाता है। यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। ओडिशा जैसे अन्य राज्यों से भी लोग यहां दर्शन के लिए आते हैं। दिन-प्रतिदिन यह एक प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल बनता जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है रायगढ़ से काफी दूरी पर लेकिन सबली जिले में आने वाले चंद्रपुर की छोटी सी पहाड़ी के ऊपर विराजित है मां चंद्रहासिनी। देवी मां चंद्रहासिनी को समर्पित मंदिर महानदी के तट पर स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर जिले में स्थित, चंद्रहासिनी देवी मंदिर रायगढ़ के आसपास के स्थानों की खोज करने वाले पर्यटकों के लिए एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। यहां आने वाले दैनिक अनुष्ठानों के अलावा, मंदिर विशेष रूप से उन पूजाओं के लिए जाना जाता है जो नवरात्रि

के दिनों में यहां आयोजित की जाती हैं। नवरात्रि के नौ दिनों में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक होती है। मंदिर परिसर में अर्द्धनारीश्वर, महाबलशाली पवन पुत्र, कृष्ण लीला, चौरहरण, महिषासुर वध, वारों धाम, नवग्रह की मूर्तियां, सर्वधर्म सभा, शेषनाग शाला तथा अन्य देवी-देवताओं की भव्य मूर्तियां जीवन्त लगती हैं। इसके अलावा मंदिर परिसर में ही स्थित चलित झांकी महाभारत काल का सजीव चित्रण है, जिसे देखकर महाभारत के चरित्र और कथा की विस्तार से जानकारी भी मिलती है। दूसरी ओर भूमि के अंदर बनी सुरंग रहस्यमयी लगती है और इसका भ्रमण करने पर रोमांच महसूस होता है। वहीं माता चंद्रसेनी की चंद्रमा आकार प्रतिमा के एक दर्शन मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चंद्रहासिनी माता का मुख मंडल चांदी से चमकता है, वे नजारा देश भर के अन्य मंदिरों में दुर्लभ है।



मां नाथलदाई

चंद्रहासिनी मंदिर से लगभग डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर माता नाथलदाई का मंदिर है जो की रायगढ़ जिले की सीमा अंतर्गत आता है। महानदी के बीच मां नाथलदाई का मंदिर स्थित है, जो की रायगढ़ जिले की सीमा अंतर्गत आता है। कहा जाता है कि मां चंद्रहासिनी के दर्शन के बाद माता नाथलदाई के दर्शन भी जरूरी है। अन्यथा माता नाराज हो जाती है। महानदी में बरसात के दौरान लंबालब पानी भरे होने के बाद भी मां नाथलदाई का मंदिर नहीं डूबता। साथ ही यहां चंद्रपुर किला भी देखने लायक है। 1400 और 1500 के दशक में गोंड राजाओं ने इस किले का निर्माण एक महत्वपूर्ण रक्षा व्यवस्था के रूप में करवाया था। इसकी दीवारों और प्रवेश द्वार गोंड शिल्प कौशल और युद्ध कौशल का बेहतरीन उदाहरण हैं।

मां बमलेश्वरी मंदिर, डोंगरगढ़, राजनांदगांव

राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ की 16 सौ फीट ऊंची पहाड़ी पर मां बमलेश्वरी माता का भव्य मंदिर विराजमान है। मंदिर की अधिष्ठात्री देवी मां बगलामुखी जी हैं, जिन्हें मां दुर्गा का स्वरूप भी माना जाता है। हजार से ज्यादा सीढ़ियां चढ़कर हर दिन मां के दर्शन पाने के लिए पूरे देश के कोने-कोने से श्रद्धालु यहां आया करते हैं। जो ऊपर नहीं चढ़ पाते उनके लिए मां का एक मंदिर पहाड़ी के नीचे भी स्थित है जिसे छोटी बमलेश्वरी मां के रूप में जाना जाता है। अब मां के मंदिर में जाने के लिए रोप वे भी लगाया जा चुका है। ऊपर बड़ी बमलेश्वरी एवं नीचे स्थित छोटी बमलेश्वरी माता विराजित हैं। इन्हें एक-दूसरे की बहन भी कहा जाता है। मंदिर के नीचे छपरानी नामक एक जलाशय भी है जहां रात्रियों के लिए बोटिंग की व्यवस्था भी उपलब्ध है। डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी माता के दो मंदिरों के अलावा मां बजरंगबली मंदिर, नाग वासुकी मंदिर, शीतला मंदिर तथा दादी मां मंदिर भी स्थित हैं। मंदिर का दरवाजा सुबह चार बजे से दोपहर के एक बजे तक तथा फिर दोपहर दो बजे से लेकर रात के 10 बजे तक खुला रहता है। राखीय को सुबह चार बजे से रात दस बजे तक मंदिर लगातार खुला ही रहता है। नवरात्रि के दिनों में अधिक भीड़ होने के वजह से पर मंदिर

का पट चौबीसों घंटे खुला रहता है। यहां सच्चे मन से मांगी की हर एक मुद्रा मां जरूर पूरा कर देती है। वही वजह है कि नवरात्रि के दिनों में यहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता के श्रीचरणों में अक्षीयार्द्र लेने के लिए दूर दूर से आते हैं। अष्टमी पर माता के दर्शन करने छोटी लाइन पर थड़ा रहना भी पड़ता है। इसके बावजूद भी यहां हर साल भीड़ बढ़ती ही जाती है। बड़ी संख्या में यहां श्रद्धालु पैदल भी माता के दरबार में पहुंचते हैं।

2200 साल पुराना है मंदिर का इतिहास

कहा जाता है कि लगभग 22 सौ साल पहले मंदिर का निर्माण हुआ था। डोंगरगढ़ से प्राप्त भग्नावशेषों से प्राचीन कामावती नगरी होने के प्रमाण मिले हैं। पूर्व में डोंगरगढ़ ही वैभवशाली कामाख्या नगरी कहलाती थी। मां बमलेश्वरी मंदिर के इतिहास को लेकर कोई स्पष्ट तथ्य तो मौजूद नहीं है, लेकिन मंदिर के इतिहास को लेकर जो पुरातंत्र और दस्तावेज सामने आए हैं, उसके मुताबिक डोंगरगढ़ का इतिहास मध्यप्रदेश के उज्जैन से जुड़ा हुआ है। मां बमलेश्वरी को मध्यप्रदेश के उज्जैन की प्रतापी राजा विक्रमादित्य की कुल देवी भी कहा जाता है। इतिहासकारों और विद्वानों ने इस क्षेत्र को कल्चरी काल का पाया है, लेकिन अन्य उपलब्ध सामग्री जैसे जैन मूर्तियां यहां दो बार



मिल चुकी हैं, तथा उससे हटकर कुछ मूर्तियों के गहने, उनके वस्त्र, आभूषण, मोटे लोठों तथा मस्तक के लम्बे बालों की सूक्ष्म मीमांसा चित्रण पर इस क्षेत्र की मूर्ति कला पर गोंड कला का प्रमाण परिलक्षित हुआ है। मां बमलेश्वरी को मध्यप्रदेश के उज्जैन की प्रतापी राजा विक्रमादित्य की कुल देवी भी कहा जाता है। आज भी पहाड़ी में किले के बने हुए अवशेष बाक़ी हैं। इसी वजह से इस स्थान का नाम डोंगरगढ़ (गोंगर, पहाड़, गढ़, किला) रखा गया और मां बमलेश्वरी का मंदिर चोटी पर स्थापित किया गया।

गर्भावस्था में संक्रमणों से रहें सतर्क

नई स्टडी में ऑटिज्म और बौद्धिक अक्षमता से जुड़े खतरों की आशंका

गर्भावस्था के दौरान माँ की सेहत का असर गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास पर पड़ता है। इसी दिशा में हुई एक बड़ी स्टडी ने कुछ दुर्लभ संक्रमणों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी सामने रखी है। शोध में पाया गया कि जन्म के समय TORCH संक्रमण से प्रभावित बच्चों में आगे चलकर ऑटिज्म और बौद्धिक अक्षमता की पहचान का जोखिम सामान्य बच्चों की तुलना में अधिक देखा गया। यह निष्कर्ष लंबे समय तक किए गए स्वास्थ्य रिकॉर्ड के अध्ययन पर आधारित है। शोधकर्ताओं ने 1987 से 2021 के बीच जन्मे करीब 36.66 लाख लोगों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड का विश्लेषण किया। इनमें 975 लोगों ने जन्मजात TORCH संक्रमण दर्ज था। इन लोगों के स्वास्थ्य और विकास से जुड़े आंकड़ों को कई वर्षों तक देखा गया। अध्ययन में TORCH संक्रमण वाले बच्चों में बाद के जीवन में ऑटिज्म की पहचान का जोखिम बिना संक्रमण वाले बच्चों की तुलना में करीब तीन गुना पाया गया। बौद्धिक अक्षमता के मामले में यह संबंध और अधिक मजबूत था। इसका जोखिम सात गुना से ज्यादा देखा गया। हालांकि इन आंकड़ों का समझने में सावधानी जरूरी है। TORCH संक्रमण दुर्लभ होते हैं और संक्रमण से प्रभावित हर बच्चे में ऑटिज्म या बौद्धिक अक्षमता विकसित हो, ऐसा जरूरी नहीं है। स्टडी संक्रमण और बाद की स्वास्थ्य स्थितियों के बीच संबंध बताती है, इसे किसी एक व्यक्ति के भविष्य की निश्चित भविष्यवाणी नहीं माना जा सकता।

क्या है TORCH संक्रमण और गर्भ में बच्चे तक कैसे पहुंचता है?

TORCH किसी एक बीमारी का नाम नहीं है। यह कुछ ऐसे संक्रमणों के समूह के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, जो गर्भावस्था के दौरान माँ से भ्रूण तक पहुंच सकते हैं। इसके तहत टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रुबेला, साइटोमेगालोवायरस और हर्पीस जैसे संक्रमण शामिल किए जाते हैं। इन संक्रमणों की घिंता इसलिए अधिक होती है क्योंकि कुछ रोगजनक प्लेसेंटा को पार करके भ्रूण तक पहुंच सकते हैं। संक्रमण का असर गर्भावस्था के समय, संक्रमण के प्रकार और दूसरे स्वास्थ्य कारकों पर निर्भर कर सकता है। नई स्टडी में पाया गया कि जन्मजात TORCH संक्रमण वाले बच्चों में केवल ऑटिज्म ही नहीं, बल्कि बौद्धिक अक्षमता के अलग-अलग स्तरों का जोखिम भी अधिक था। हल्की से लेकर गंभीर बौद्धिक अक्षमता तक के मामलों में संबंध देखा गया। गंभीर और बेहद गंभीर बौद्धिक अक्षमता के मामलों में यह संबंध सबसे मजबूत पाया गया। शोध में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई। जिन बच्चों में ऑटिज्म के साथ बौद्धिक अक्षमता भी दर्ज थी, उनमें संक्रमण और स्थिति के बीच संबंध उन बच्चों की तुलना में अधिक पाया गया जिनमें केवल ऑटिज्म की पहचान हुई थी।



स्कूल प्रदर्शन में भी दिखाई दिया अंतर

शोधकर्ताओं ने केवल मेडिकल रिकॉर्ड तक अध्ययन को सीमित नहीं रखा, बल्कि बच्चों की शिक्षा से जुड़े रिकॉर्ड का भी विश्लेषण किया। TORCH संक्रमण वाले लोगों के किशोरावस्था के दौरान स्कूल ग्रेड औसतन कुछ कम पाए गए। दिलचस्प बात यह रही कि यह अंतर उन लोगों में भी देखा गया जिनमें ऑटिज्म या बौद्धिक अक्षमता की कोई दर्ज पहचान नहीं थी। इससे शोधकर्ताओं को यह समझने में मदद मिलती है कि जन्मजात संक्रमण का प्रभाव केवल स्पष्ट न्यूरोडेवलपमेंटल स्थितियों तक सीमित हो सकता है या विकास और सीखने के दूसरे पहलुओं से भी उसका संबंध हो सकता है। फिर भी यहां भी सीधे कारण और परिणाम का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। किसी बच्चे के सीखने और विकास पर आनुवंशिक, सामाजिक, स्वास्थ्य संबंधी और पर्यावरणीय कई कारकों का प्रभाव हो सकता है।

तनाव को लेकर भी जरूरी है सही समझ

गर्भावस्था के दौरान तनाव को लेकर अक्सर महिलाओं में डर पैदा हो जाता है। तनाव कम रखना माँ और बच्चे दोनों के लिए अच्छा है, लेकिन इसे ऑटिज्म का सीधा कारण मानना वैज्ञानिक रूप से उचित नहीं है। लगातार तनाव नींद, भोजन, ब्लड प्रेशर और माँ के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, इसलिए जरूरत पड़ने पर परिवार और स्वास्थ्य विशेषज्ञ से मदद लेना बेहतर है। इसी तरह समय से पहले जन्म और कम वजन वाले बच्चों में कुछ न्यूरोडेवलपमेंटल समस्याओं का जोखिम अधिक देखा जा सकता है। ऐसे बच्चों के विकास की नियमित निगरानी और समय पर विकासात्मक जांच महत्वपूर्ण हो जाती है।



ऑटिज्म को लेकर इन बातों पर ध्यान देना जरूरी

ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरोडेवलपमेंटल स्थिति है, जो व्यक्ति के संचार, व्यवहार और सामाजिक संपर्क के तरीके को प्रभावित कर सकती है। इसके पीछे किसी एक कारण को जिम्मेदार नहीं माना जाता। आनुवंशिक और पर्यावरणीय कई कारक मिलकर भूमिका निभा सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान कुछ स्थितियों को बच्चे के न्यूरोडेवलपमेंट से जोड़ा गया है। इनमें मां की कुछ स्वास्थ्य समस्याएं, कुछ संक्रमण, समय से पहले जन्म और जन्म के समय कम वजन जैसे कारक शामिल हैं। हालांकि किसी एक कारक का मौजूदगी का अर्थ यह नहीं है कि बच्चे को निश्चित रूप से ऑटिज्म होगा।

- आनुवंशिक कारक: ऑटिज्म के विकास में आनुवंशिक भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। परिवार में ऑटिज्म या कुछ अन्य न्यूरोडेवलपमेंटल स्थितियों का इतिहास होने पर डॉक्टर अतिरिक्त निगरानी को सलाह दे सकते हैं।
- गर्भावस्था से जुड़ी स्वास्थ्य स्थितियाँ: गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज, अल्ब्यूमिन व्रजन या हाई ब्लड प्रेशर जैसी स्थितियों का उचित प्रबंधन मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है।
- संक्रमण से बचाव: रुबेला जैसे संक्रमणों से बचाव, जल्दी टीकाकरण और डॉक्टर की सलाह के अनुसार जांच गर्भावस्था की देखभाल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसी संक्रमण के लक्षण दिखाई देने पर स्वयं दवा लेने के बजाय चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी है।
- दवाओं का इस्तेमाल: गर्भावस्था में कुछ दवाओं के इस्तेमाल को लेकर विशेष सावधानी की जरूरत होती है। वैलप्रोइक एसिड जैसी कुछ दवाओं के गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव को लेकर चिकित्सकीय प्रमाण मौजूद हैं। इसलिए गर्भावस्था की जानकारी होने पर दवा शुरू करने, बंद करने या उसकी मात्रा बदलने का फैसला डॉक्टर की सलाह से ही किया जाना चाहिए।
- प्रदूषण और रसायनों से बचाव: वायु प्रदूषण तथा कुछ रासायनिक पदार्थों के लंबे समय तक संपर्क को लेकर भी शोध जारी है। इसलिए गर्भावस्था में अनावश्यक रासायनिक संपर्क से बचना और सुरक्षित वातावरण बनाए रखना उपयोगी है।

रोकथाम का सबसे मजबूत रास्ता है बेहतर प्रीनेटल केयर

नई स्टडी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश डर पैदा करना नहीं, बल्कि जागरूकता बढ़ाना है। गर्भावस्था की नियमित जांच, संक्रमण से बचाव, जरूरी टीकाकरण, पहले से मौजूद बीमारियों का नियंत्रण, संतुलित पोषण और डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाओं का इस्तेमाल मां और बच्चे दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। TORCH संक्रमण दुर्लभ है, इसलिए केवल इस अध्ययन के आधार पर गर्भवती महिलाओं को अनावश्यक चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी संक्रमण का पता चलने पर भी यह मान लेना सही नहीं होगा कि बच्चे को आगे चलकर ऑटिज्म या बौद्धिक अक्षमता निश्चित रूप से होगी। सबसे जरूरी बात यह है कि गर्भावस्था को डर की नहीं, नियमित देखभाल और सही जानकारी की जरूरत है। समय पर चिकित्सकीय सलाह, उचित जांच और मां की स्वास्थ्य स्थिति पर नज़र रखने से गर्भावस्था से जुड़े कई जोशिमों को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है। वहीं बच्चे के जन्म के बाद उसके विकास, भाषा, सीखने और व्यवहार में किसी तरह की चिंता दिखाई दे तो जल्द विशेषज्ञ से सलाह लेना शुरूआती सहायता के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है।

अभिनय नहीं, किरदार की आत्मा बन जाते थे नाना

पर्दे पर आग, जिंदगी में इंसानियत और उदय शेट्टी की बेमिसाल हंसी

कुछ कलाकार अपने किरदारों से पहचाने जाते हैं, कुछ अपनी आवाज से और कुछ अपने दौर से। नाना पाटेकर इन तीनों सीमाओं से आगे थे। वह अभिनय की ऐसी पाठशाला थे, जहां आंखों का ठहराव संवाद से अधिक बोलता था, खामोशी में भी विस्फोट सुनाई देता था और एक अक्खड़ चेहरे के भीतर कर्षण का अथाह संसार छिपा रहता था। आठ अक्टूबर को 75 वर्ष की उम्र में उनका जाना हिंदी और मराठी सिनेमा के लिए ऐसी रिक्तता छोड़ गया है, जिसे केवल फिल्मों की सूची गिनाकर नहीं भरा जा सकता।

नाना पाटेकर को पर्दे पर देखते हुए अक्सर लगता था कि वह अभिनय नहीं कर रहे, बल्कि उस किरदार की जिंदगी जी रहे हैं। उनकी आवाज में खुरदरापन था,

संवाद अदायगी में धार और चैहरे पर भावों की ऐसी वारीकियां कि एक नजर ही पूरे दृश्य का अर्थ बदल देती थी। वह बिना अनावश्यक नाटकीयता के क्रोध पैदा कर सकते थे, बिना आंसूओं के दुःख जगा सकते थे और एक ठहरी हुई निगाह से दर्शक को असहज कर सकते थे। 'अंकुश' से शुरू हुआ उनका सफर 'परिंदे', 'प्रहार', 'कालिवीर', 'अब तक छप्पन' और 'नटसम्राट' जैसी फिल्मों में अलग-अलग रंग लेकर सामने आया। कहीं वह व्यवस्था से भिड़ता आक्रोश थे, कहीं हिंसा के अंधेरे में उलझा मनुष्य, तो कहीं दृढ़ आत्मसम्मान की लड़ाई। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित और पद्मश्री से अलंकृत इस कलाकार ने साबित किया कि अभिनय की ताकत चैहरे की सुंदरता या संवादों की लंबाई में नहीं, बल्कि किरदार को भीतर तक समझने में होती है।

गुस्सैल अभिनेता
के भीतर छिपा
हास्य सम्राट

नाना की अदाकारी की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि गंभीर और आक्रामक भूमिकाओं में अपनी अलग पहचान बनाने वाला वह कलाकार कॉमेडी में भी उतना ही अनुकूल निकला। 'वेलकम' का उदय शेट्टी इसका सबसे खादमा उदाहरण है। सोचिए, वही चेहरा जो 'कालिवीर' में व्याघ्रस्था की ललकारता है, वही आवाज जो 'प्रहार' में सैनिक अनुशासन का भार उठाती है, 'वेलकम' में गैंगस्टर उदय शेट्टी बनकर ऐसी हास्य स्थितियां रचती है कि दर्शक हंसी से बेताल हो जाते हैं। 'कंदील उदय, कंदील' केवल एक संवाद नहीं रहा, बल्कि लोकप्रिय संस्कृति का हिस्सा बन गया। इस किरदार की खुबी सिर्फ संवादों में नहीं थी। नाना का चेहरा, उनका ठहराव, बात-बात पर उभरती झुंझलाहट और अपने ही रीढ़ में उलझ जाने का अंदाज, सब मिलकर उदय शेट्टी का अविस्मरणीय बनाते हैं। उनकी कॉमेडी में अलग से हंसाने की कोशिश नहीं दिखती थी। हास्य उनके स्वभाव, प्रतिक्रिया और संवाद के बीच से निकलता था। उही कारण है कि उनके कई गंभीर किरदारों की तरह उदय शेट्टी भी दर्शकों की स्मृति में स्थायी जगह बना चुका है।





प्रसिद्धि से दूर, जिम्मेदारी के करीब

नाना की शरियत में एक धिरोभास हमेशा दिखाई दिया। वह अपनी बेबाकी और तीखे मिजाज के लिए जाने जाते थे, लेकिन सामाजिक सरोकारों के मामले में उनका व्यवहार संवेदनशील रहा। सेना के प्रति सम्मान, किसानों की मदद और निशानेबाजी जैसे क्षेत्रों में उनकी सक्रियता बताती है कि उनकी दिलचस्पियाँ फिल्मों दुनिया तक सीमित नहीं थीं। क्रिकेट से उनका लगाव भी जगजाहिर था। धिराट कोहली के प्रशंसक नाना खेल को भी उसी जुनून से देखते थे, जिस जुनून से अपने किरदारों को निभाते थे। उनकी जिंदगी को किसी एक विशेषण में समेटना मुश्किल है। वह एक अभिनेता थे, लेकिन केवल अभिनेता नहीं। वह निशानेबाज थे, लेकिन केवल पदक जीतने वाले खिलाड़ी नहीं। वह समाजसेवा से जुड़े थे, लेकिन उनकी पहचान केवल दान तक सीमित नहीं थी। उनकी असली विशेषता शायद यही थी कि जिस काम को अपनाया, उसमें पूरी गंभीरता से उतरे।

राइफल के निशाने पर भी साधा कमाल

नाना की जिंदगी का एक कम चर्चित पक्ष निशानेबाजी था। पद पर हथियार धामना एक बात है, लेकिन असल जिंदगी में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उतरना दूसरी। चालीस वर्ष की उम्र पार करने के बाद राइफल शूटिंग में उनकी रुचि बढ़ी और उन्होंने इसे गंभीरता से अपनाया। वर्ष 2004 में इंदौर में हुई राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में उन्होंने 300 मीटर ब्रिग-बोर स्पर्धा में रजत पदक जीता। 2007 में महाराष्ट्र की टीम के साथ इसी स्पर्धा में कोयंबट पदक हासिल किया। उनके प्रदर्शन ने उन्हें 'रेनाउंडेड शूट' की पहचान भी दिलाई। इस लगन के पीछे 'प्रहार' के लिए भारतीय सेना के साथ लिया गया प्रशिक्षण भी था। फिल्म की तैयारी ने उन्हें सेना अनुशासन और हथियारों के इस्तेमाल को करीब से समझने का अवसर दिया। लेकिन नाना ने उस अनुभव को केवल अभिनय तक सीमित नहीं रखा। निशानेबाजी में उन्होंने बाकायदा अभ्यास किया, प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और अपनी अलग पहचान बनाई। उनके लिए यह किसी सितारे का शौक भर नहीं, बल्कि सीधे और खुद को लगातार चुनौती देने का माध्यम था।

विरासत, जो पर्दा गिरने के बाद भी जीवित रहेगी

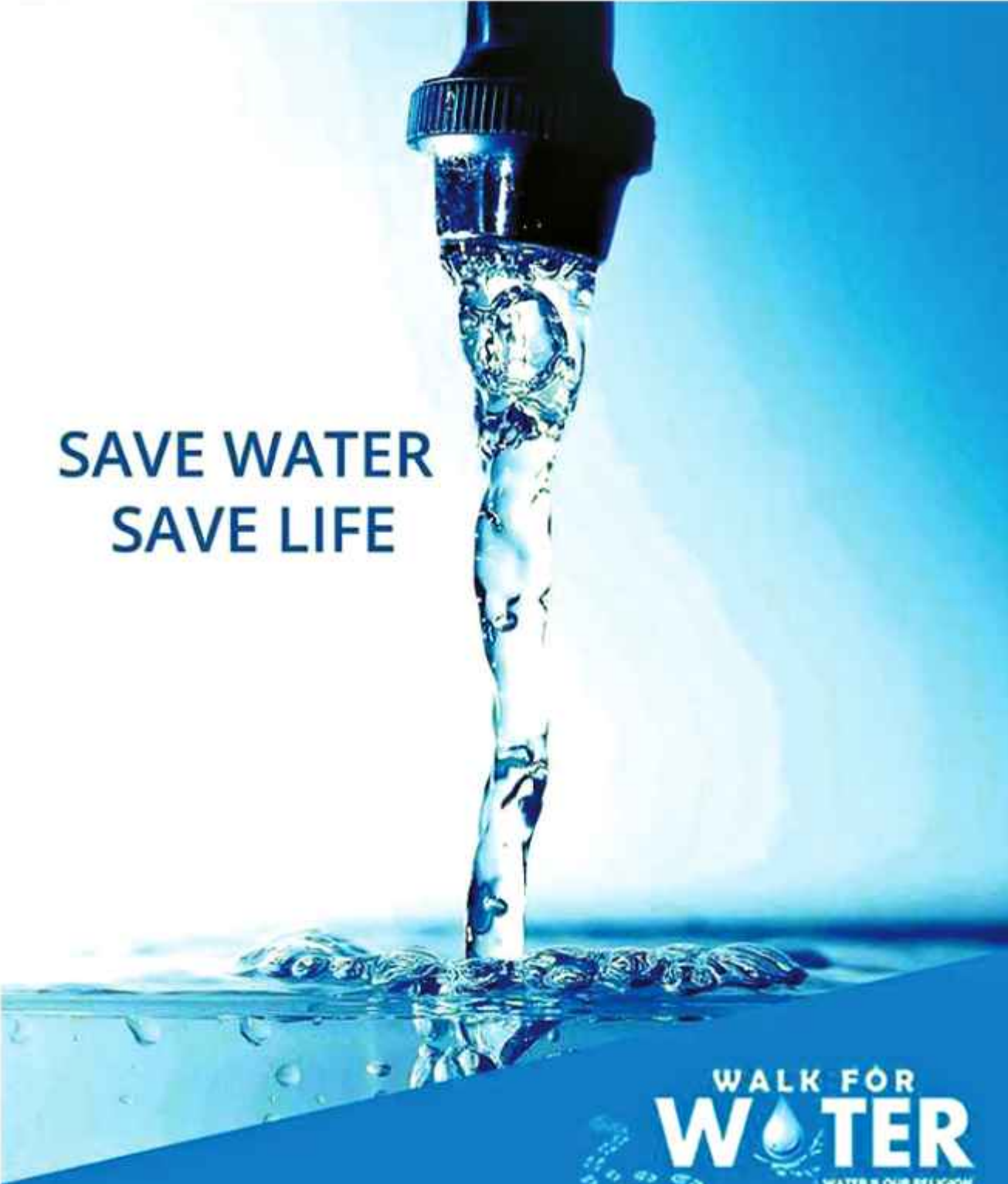
नाना पाटेकर के जाने के बाद उनकी फिल्मों के दृश्य, संवाद और चेहरे के अनगिनत भाव फिर राद किए जाएंगे। कोई 'कॉन्ट्री' के तेवर राद करेगा, कोई 'नटसमाट' की पीड़ा, कोई 'परदा' का अंधेरा और कोई 'वेलकम' के उदर श्रेणी की शरारत भरी अकड़। लेकिन उनकी विरासत का एक हिस्सा उन गांवों में भी मौजूद रहेगा, जहाँ पानी बचाने और किसान परिवारों को सहारा देने की कोशिशें जारी हैं। कलाकार की उम्र उसके शरीर के साथ समाप्त हो सकती है, लेकिन उसके काम की उम्र कहीं लंबी होती है। नाना ने पद पर ऐसे किरदार छोड़े, जो बार-बार देखे जाएंगे; और जीवन में ऐसे काम किए, जो दूसरों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकते हैं। उनकी विदाई पर सबसे सच्ची श्रद्धांजलि शायद यही है कि हम उन्हें केवल उनके तीखे संवादों या लोकप्रिय दृश्यों तक सीमित न रखें। उन्हें उस कलाकार के रूप में राद करें, जिसने अभिनय की सीमाओं को चुनौती दी, अपनी रुचियों को उम्र के बंधन में नहीं बाँधा और दूसरों के दर्द को अन्वेषण करने के बजाय उसके बीच पहुँचने की कोशिश की। नाना पाटेकर का पर्दा गिर गया है, लेकिन उनके किरदारों की गूंज, उदर श्रेणी की हंसी और इंसानियत के लिए उठाए गए उनके कदम लंबे समय तक हमारे बीच बने रहेंगे।

जब लगजरी कार से अधिक जरूरी लगा किसान का दर्द

नाना के व्यक्तित्व का एक और पक्ष महाराष्ट्र के किसानों के प्रति उनकी संवेदना थी। वर्ष 2015 में मराठवाड़ा और विदर्भ सूखे, फसल बर्बादी और किसान परिवारों की मुश्किलों से जुड़ा रहे थे। ऐसे समय में नाना ने अभिनेता मकरंद अनासपुरे के साथ मिलकर मदद का रास्ता चुना। मौडिया में आई खबरों के अनुसार, महंगी कार खरीदने के लिए रखी गई रकम को किसान परिवारों की सहायता में लगाने का निर्णय भी इसी दौर से जुड़ा है। 15 सितंबर 2015 को दोनों ने नाम फाउंडेशन की शुरुआत की। संस्था का काम केवल तत्काल राहत तक सीमित नहीं रहा। जल संरक्षण, सूखते जलस्रोतों के पुनर्जीवन, ग्रामीण आजीविका और संकटग्रस्त किसान परिवारों की मदद जैसे विषय उसके काम के केंद्र में आए। नाना की इस पहल का महत्व सिर्फ आर्थिक सहायता में नहीं था। उन्होंने उस पीड़ा की ओर ध्यान खींचा, जो अक्सर सुर्खियों से उतर जाने के बाद भी गांवों में बनी रहती है। किसान की समस्या किसी एक मौसम की नहीं होती। पानी, कर्ज, खेती की लागत, बाजार और परिवार की जिम्मेदारियाँ मिलकर उसे घेरती हैं। नाना ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल इस संकट को सामने लाने और सहायता जुटाने के लिए किया। यही वह जगह थी, जहाँ पदों का नश्वर वास्तविक जीवन के संघर्षों के साथ खड़ा दिखाई देता है।

एक्ट्रेस अनीत पट्टा का लेटेस्ट ग्लैमरस फोटोशूट को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में है। अनीत पट्टा ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। पोस्ट के साथ उन्होंने "rust & stardust" कैप्शन लिखा। तस्वीरों में उनका स्टायलिश अंदाज नजर आया, जिसे फैस और सोशल मीडिया यूजर्स खूब पसंद कर रहे हैं। इन तस्वीरों में एक्ट्रेस का स्टायलिश और खूबसूरत अंदाज देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि अनीत पट्टा 'सलाम वैकी' में नजर आई थीं। उन्हें सबसे ज्यादा पहचान 'सेवारा' से मिली थी। इसमें उनके साथ अहान पोंडे थे। जल्द ही वह फिल्म 'शक्ति शालिनी' का हिस्सा होंगी। अनीत पट्टा की नई वेब सीरीज 'हुंकार' पिछले महीने रिलीज हुई। इसमें वह बापजी के खिलाफ आवाज उठाती नजर आई, जो बहुत प्रभावशाली है। सीरीज में उनके साथ फातिमा सना शेख हैं, जो कैस की जांच करती हैं।





SAVE WATER
SAVE LIFE

WALK FOR
WATER
WATER IS OUR RELIGION

जनता के गोठ

जहां खबर नहीं, असर होता है



सेवा के
25वर्ष
सुरक्षण । प्रतिव कल्याण । राष्ट्र निर्माण

सेवा सेतु

जनता के द्वार, डिजिटल सरकार

दफ्तरों के चक्कर खत्म



अधिक
जानकारी हेतु
► स्कैन करें
या विजिट करें

sewasetu.cgstate.gov.in

92034 06400

